https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

प्रधानमंत्री द्वारा प्रयागराज में नए हवाई अड्डा परिसर का शुभारंभ

वर्ष-14, अंक-01 01-15 जनवरी, 2019 (पाक्षिक) ₹20

‘विकास है भाजपा का मंत्र’

समय की मांग है सहमति की राजनीति | अटल जीः एक अनूठे सांसद | राफेल पर कांग्रेस गढ़ रही है झूठ का पुलिंदा

नई दिल्ली में आयोजित विशाल बूथ सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलन कर उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और साथ में दिल्ली प्रदेश वरिष्ठ भाजपा नेतागण

राजकोट (गुजरात) में अर्श विद्या मंदिर परिसर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह व अन्य

नई दिल्ली में भाजयुमो द्वारा आयोजित 'विजय लक्ष्य 2019' राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन और मंच पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव व अन्य

बिहार में राजग को मजबूत करने हेतु बुलाई गई बैठक के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान व अन्य

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह से मिलते भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल जैन और हरियाणा में हालिया चुने गए पांच शहरों के मेयरगण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 युवा मोर्चा ठान ले तो कोई भी 'सबका साथ-सबका विकास' के लक्ष्य की पूर्ति में अड़चन साबित नहीं हो सकता: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को देशभर से आये युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से 2019 में लोक सभा चुनाव...

वैचारिकी

राष्ट्र के वैभव में व्यक्ति का वैभव 14

श्रद्धांजलि

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 17

लेख

समय की मांग है सहमति की राजनीति 18

अटल जी: एक अनूठे सांसद 20

राफेल पर कांग्रेस गढ़ रही है झूठ का पुलिंदा 22

राफेल मुद्दे पर जारी निरर्थक बहस 24

अन्य

राजीव प्रताप रूडी बने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता 07

भाजपा ने असम और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की 09

नवंबर में खुदरा महंगाई डेढ़ साल के निचले स्तर 2.33% पर 12

प्रधानमंत्री ने रायबरेली में विभिन्न विकास परियोजनाएं आरम्भ कीं 13

नेशनल हेराल्ड के नाम पर 'एक परिवार' द्वारा हेराफेरी 26

'विपक्ष चाहे जितनी भ्रांतियां फैलाए, केंद्र में सरकार भाजपा की ही बनेगी' 27

2014 के बाद से पूर्वोत्तर में विद्रोह की घटनाओं में 63 प्रतिशत की गिरावट 30

08 भाजपा ने हरियाणा निकाय चुनावों में लहराया जीत का परचम

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच महापौर पदों...

10 सत्य की जीत हुई : अमित शाह

भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को अहम फैसला सुनाया। सीजेआई श्री रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली...

11 जीएसटी परिषद द्वारा नववर्ष का बड़ा तोहफा

जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट...

32 दिवाला और शोधन अक्षमता कोड में संशोधन हुआ

सभी हितधारकों को अधिक व्यापार सुगमता प्रदान करने, कार्पोरेट ढांचे में अधिक पारदर्शिता लाने...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए हर रक्षा सौदे में कोई न कोई विदेशी मामा, अंकल, चाचा-भतीजा निकल आता है। इसलिए जब पारदर्शिता और ईमानदारी से सौदे होते हैं, तो कांग्रेस बौखला जाती है।

@AmitShah

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अदालत द्वारा आजीवन कैद की सजा दिए जाने से कांग्रेसियों का दोहरा चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया है और यह सिद्ध हो गया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे तत्कालीन सत्ताधीशों की निगरानी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ही किये गए थे।

@byadavbjp

प. बंगाल में भाजपा की गणतंत्र बचाओ यात्रा पर ममता सरकार द्वारा रोक जैसा अलोकतांत्रिक निर्णय अगर कोई भाजपा शासित राज्य ले लेता तो अभिव्यक्ति की आजादी के पैरवीकार इसे अब तक 'अघोषित आपातकाल' और न जाने क्या-क्या संज्ञा दे देते लेकिन अब मानो इन आजादी के पैरवीकारों को सांप सूंघ गया हो।

facebook

सियासी लाभ के लिए, राफ़ेल डील के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी ख़राब करने की कोशिश की। यह एक अपराध है। संसद में आकर कांग्रेस अध्यक्ष देश से क्षमा मांगे। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप रहे हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सारी पीआइएल ख़ारिज करते हुए कहा है कि डील में सन्देह की कोई गुंजाईश नहीं है।

— राजनाथ सिंह

केन्द्र सरकार ने पिरूल को मनरेगा से जोड़ने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है। राज्य में अब पिरूल बेरोजगारी दूर करने तथा आय के संसाधनों में वृद्धि में भी मददगार होगा। इससे 143 प्रकार के आइटम तैयार किये जा सकते है। सहकारिता से भी इससे संबंधित योजनाओं को जोड़ा जायेगा।

—त्रिवेंद्र सिंह रावत

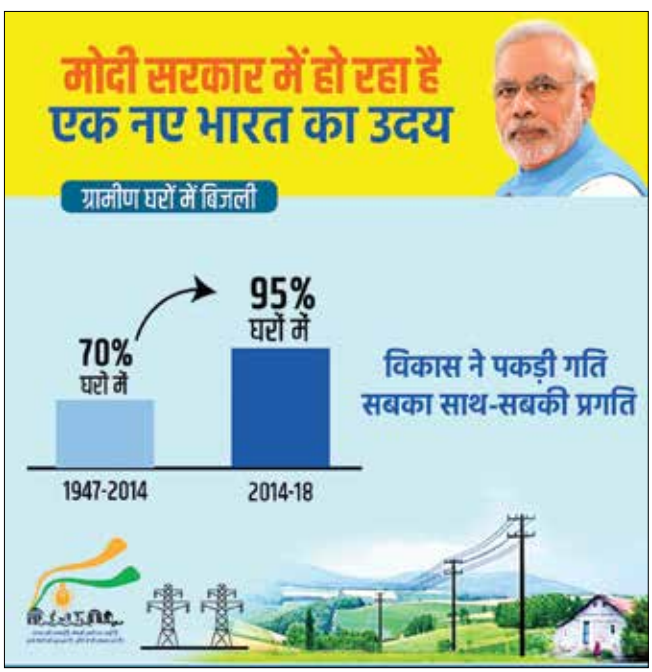

कांग्रेस करती है झूठ एवं फरेब की राजनीति

कांग्रेस एक बार पुनः बेनकाब हो गई है। इसकी झूठ एवं फरेब की राजनीति एक बार फिर से जगजाहिर हुई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल समझौते पर इसके झूठे प्रचार की पोल खोल कर रख दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि झूठ एवं फरेब की राजनीति से कांग्रेस अपनी छवि नहीं सुधार सकती। कांग्रेस जो भ्रष्टाचार, कुशासन, नीतिगत पंगुता एवं लूट–खसोट की राजनीति की पर्याय बन चुकी है, अब दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपने पाप नहीं धो सकती। भाजपा की बेदाग छवि और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ईमानदारी एवं कर्मठता पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता और यह बारंबार प्रमाणित भी हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन किया और उनकी धवल कीर्ति उनके मां भारती की सेवा में निरंतर निस्वार्थ भाव से समर्पण का प्रमाण है। राफेल पर निराधार आरोप लगाकर कांग्रेस ने स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब वह केवल स्वयं को कोस सकती है।

झूठ और फरेब की राजनीति का जीवन बहुत छोटा होता है और सच्चाई की कसौटी पर इसकी हार हो जाती है। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस झूठ एवं फरेब की राजनीति का सहारा लेकर सत्ता में आना चाहती है, परन्तु सत्य की कसौटी पर बार–बार बेनकाब हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय जगत में मान्यता मिल रही है।

यह कोई पहली बार नहीं कि कांग्रेस ने झूठ एवं फरेब की राजनीति की है। यह निरंतर निराधार आरोपों के आधार पर जनता को दिग्भ्रमित करने के कुप्रयासों में लगी हुई है। वास्तव में यह एक चाल है, जिसके जरिए कांग्रेस के अतीत के गुनाहों एवं कुकर्मों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पूर्व में भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इसने श्री नरेन्द्र मोदी एवं श्री अमित शाह पर कई मनगढ़न्त आरोप लगाने का प्रयास किया, परन्तु हर बार इसे न्यायालयों में मुंह की खानी पड़ी। हाल ही में न्यायमूर्ति लोया के निधन को लेकर बहुत हो–हल्ला मचाया गया और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के विरुद्ध व्यापक षड्यंत्र रचा गया। यह बड़ी विडंबना थी कि बिना किसी तथ्य के आरोप गढ़े गये जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया और कांग्रेसी दुष्प्रचार की पोल खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, अनेक राष्ट्रीय विषयों पर भी कांग्रेस ने झूठ एवं फरेब की राजनीति का सहारा लेना चाहा, भले ही इससे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को क्षति पहुंचे। राफेल इसका ऐसा ही एक उदाहरण है, जिसमें यह जानते हुए भी कि यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है और इससे हमारी सुरक्षा बलों के मनोबल पर प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को अपने राजनैतिक हितों की चिंता अधिक है। कांग्रेस को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसके शासन में उठाये गये लगभग सभी भ्रष्टाचार के मुद्दों को न्यायालयों ने संज्ञान में लिया एवं कड़ी फटकार लगाई, जबकि इसके ठीक उलट कांग्रेस ने जो भी मुद्दे उठाये हैं वे विभिन्न न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ऐसे कई आरोप निराधार कहते हुए खारिज कर दिया है।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी गलतियों से अब तक कोई सीख नहीं ली है। राजनीति केवल आरोप–प्रत्यारोप का खेल नहीं है। राजनीति जनसेवा के क्षेत्र में ईमानदारी, प्रामाणिकता एवं कर्मठता का नाम है। केवल एक लंबी कठिन राह पर चलकर ही इन मूल्यों पर खरा उतरा जा सकता है और इसके बाद ही पार्टी या नेतृत्व पर लोगों का विश्वास टिक पाता है। झूठ और फरेब की राजनीति का जीवन बहुत छोटा होता है और सच्चाई की कसौटी पर इसकी हार हो जाती है। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस झूठ एवं फरेब की राजनीति का सहारा लेकर सत्ता में आना चाहती है, परन्तु सत्य की कसौटी पर बार–बार बेनकाब हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय जगत में मान्यता मिल रही है। भारत आज विश्व का सबसे तेज विकास दर वाला देश बन कर उभरा है और अब विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश एक बड़े व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में आमूल–चूल विकास हो रहा है। यह नेतृत्व की कड़ी मेहनत एवं ध्येयनिष्ठ राजनीति का ही परिणाम है कि ऐसे अद्भुत परिवर्तनों का साक्षात्कार हो रहा है। आज जब एक दृढ़निश्चयी, ईमानदार, कर्मठ एवं अथक कार्य करने वाला नेतृत्व भाजपा के पास है, कांग्रेस झूठ, फरेब एवं बहकावों की राजनीति से उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

युवा मोर्चा ठान ले तो कोई भी 'सबका साथ-सबका विकास' के लक्ष्य की पूर्ति में अड़चन साबित नहीं हो सकता: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को देशभर से आये युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से 2019 में लोक सभा चुनाव जीतने का आह्वान किया। वे युवा मोर्चा के देशभर से आये 1000 से अधिक युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को भाजयुमो कार्यशाला- 'विजय लक्ष्य-2019' को दिल्ली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, नई दिल्ली में संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व युवा मोर्चा के प्रभारी श्री मुरलीधर राव भी उपस्थित थे।

कार्यशाला के समापन सत्र में बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की सेना यह सुनिश्चित करेगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किये गए सभी जन विकास के कार्यों जन-जन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि समस्त युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जनोपयोगी योजनाओं के लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों के साथ निजी संपर्क स्थापित करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम 22 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने में कामयाब हुए तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को 2014 से भी अधिक प्रचंड जीत प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि युवा मोर्चा का जोश 2019 में एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार स्थापित

@AmitShah

आज दिल्ली में @BJYM की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 'विजय लक्ष्य-2019' में देशभर से आये हमारे युवा मोर्चा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया।

करेगा और देश के लोकप्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी को एक बार पुनः प्रधनामंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि यदि युवा मोर्चा ठान ले तो कोई भी गठबंधन और महागठबंधन भाजपा के 'सबका साथ-सबका विकास' के लक्ष्य की पूर्ति में अड़चन साबित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित, निर्णायक और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने 129 से अधिक गरीब-कल्याणकारी योजनाओं के जरिये देश के लगभग 50 करोड़ लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों के घर में गैस पहुंचाना है, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से हर घर में शौचालय पहुंचा है, सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली पहुंची है, मुद्रा बैंक योजना से स्वरोजगार का अभियान चला है और अब देश के लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपये सालाना स्वास्थ्य बीमा मिली है जो उनके जीवन में उजाला लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जिस काम को कांग्रेस आजादी के 70 सालों में भी नहीं कर पाई, इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साढ़े चार वर्षों में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया जिससे किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा, स्वायल हेल्थ कार्ड, ई-मंडी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं से किसानों के जीवन में बदलाव आ रहा है।

यदि युवा मोर्चा ठान ले तो कोई भी गठबंधन और महागठबंधन भाजपा के 'सबका साथ-सबका विकास' के लक्ष्य की पूर्ति में अड़चन साबित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित, निर्णायक और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है।

भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री पूनम महाजन, सांसद ने सभी उपस्थित युवा मोर्चा पदाधिकारियों को 'कार्यकर्ता से जनता' के संपर्क का मंत्र दिया। सुश्री पूनम महाजन ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का धन्यवाद व्यक्त किया और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि युवा मोर्चा की 6 करोड़ युवा कार्यकर्ताओं फौज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पुनः विजयश्री दिलवाने के लिए तत्पर है। ■

राजीव प्रताप रूडी बने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 दिसंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। बिहार से लोकसभा सदस्य श्री रूडी पूर्व में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। श्री रूडी ने ट्वीट कर कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह को धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों के प्रसार के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी निर्वहन के लिए आशान्वित हूं।" श्री रूडी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा की अगुवाई वाली पहली राजग सरकार में मंत्री रहे हैं और मोदी सरकार में भी मंत्रीपद संभाल चुके हैं। ■

भाजपा ने हरियाणा निकाय चुनावों में लहराया जीत का परचम

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच महापौर पदों पर जीत दर्ज की है। भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार हिसार, रोहतक, यमुनानगर, पानीपत और करनाल नगर निगम सीटों पर भारी अंतर से जीतकर आए हैं, जिसके लिए 16 दिसंबर को चुनाव हुए थे। चुनावों का नतीजा 19 दिसंबर, 2018 को घोषित किया गया।

इन पांच नगर निगमों के महापौरों को राज्य में पहली बार मतदाताओं द्वारा सीधे चुना गया है। भाजपा को इन पांच नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 107 वार्डों में से 62 वार्डों पर जीत हासिल हुई। वहीं इस बार स्वतंत्र उम्मीदवार ने भी 48 सीटों पर कामयाबी दर्ज की है, यह नतीजे सभी के लिए आश्चर्य चकित करने वाले रहे। इसके अतिरिक्त जाखल मंडी (फतेहाबाद) और पुंडरी (कैथल) नगरपालिका समितियों के 13 वार्डों पर भी चुनाव संपन्न हुए।

इन चुनावों को हरियाणा में चार साल से अधिक समय से सत्ता में आसीन भाजपा सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था।

इस दौरान भाजपा ने महापौर की सभी सीटों और नगर निगमों के 107 वार्डों पर चुनाव लड़ा, जबकि बसपा और माकपा ने एक-एक सीट पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने हिसार, पानीपत और रोहतक की तीन सीटों पर चुनाव लड़ा और वोटों की संख्या के मामले में पार्टी दूसरा स्थान भी सुरक्षित नहीं कर पायी, जबकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारकर, केवल अन्य उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र करनाल में, भाजपा की महापौर उम्मीदवार रेणु बाला ने स्वतंत्र आशा वाधवा को 9348 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय लोकदल दोनों का समर्थन प्राप्त था। रेणु बाला को 69960 वोट मिले।

पानीपत में, भाजपा के उम्मीदवार अवनीत ने स्वतंत्र अंशु पाहवा को 74940 के भारी अंतर से शिकस्त दी। अवनीत को 126321 वोट मिले।

जाट बाहुल्य रोहतक में भाजपा उम्मीदवार मनमोहन गोयल ने 14776 मतों के अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार सीताराम सचदेव को

हराकर जीत दर्ज की। मनमोहन को 65822 वोट मिले।

दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माने जाने वाले रोहतक में जीत ने भाजपा को एक नयी ताकत दी है, जबकि यह चुनावी परिणाम कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन गए है। श्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे श्री दीपेंद्र हुड्डा, जो रोहतक से भी सांसद हैं, ने चुनाव के दौरान स्वतंत्र सीताराम सचदेवा को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी।

हिसार में भाजपा के गौतम सरदाना ने भी स्वतंत्र उम्मीदवार रेखा एरेन के खिलाफ आसान जीत हासिल की, स्वतंत्र उम्मीदवार रेखा एरेन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। गौतम ने 68196 वोट हासिल किए और 28091 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

यमुनानगर में भाजपा के उम्मीदवार मदन सिंह ने स्वतंत्र उम्मीदवार राकेश कुमार के खिलाफ 40678 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। जहां मदन सिंह को 91642 वोट मिले, वहीं राकेश कुमार को 50964 वोट मिले। जहां तक पांच नगर निगमों में पार्षदों / वार्ड सदस्यों के चुनाव का सवाल है, भाजपा ने हिसार में 20 वार्डों में से सात वार्डों पर, करनाल में 20 वार्डों में से 12 वार्डों पर, पानीपत में 26 वार्डों में से 22 वार्डों पर, रोहतक में कुल 22 में से आठ वार्डों पर और यमुनानगर में 22 वार्डों में से 13 वार्डों पर जीत दर्ज की।

यह चुनाव इस लिहाज से भी भाजपा के लिए खास हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो इन चुनावों में दूसरा स्थान भी हासिल नहीं कर सकी।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इन चुनावों में भाजपा की जीत को नागरिकों द्वारा अपनी सरकार के बेहतरीन प्रदर्शन को स्वीकृति बताते हुए कहा कि पांच महापौर पदों पर भाजपा की जीत बताती है कि नागरिकों ने हरियाणा में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है और हम निरंतर जनता के लिए काम करते रहेंगे। ■

भाजपा ने असम और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की

भारतीय जनता पार्टी ने असम के पंचायत चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी ने इन चुनावों में कांग्रेस और एजीपी को पीछे छोड़ते हुए, अपने अजेय प्रदर्शन को एक बार फिर दोहराया है। इसी तरह, भाजपा ने महाराष्ट्र के धूलिया निकाय चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जहां भाजपा का मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से था।

हाल ही में संपन्न असम पंचायत चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 210 जिला पंचायतों, 786 आंचलिक परिषदों, 5356 ग्राम पंचायत सदस्यों, और 817 ग्राम पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की।

दूसरी ओर, कांग्रेस को 145 जिला परिषदों, 574 आंचलिक परिषदों, 3912 ग्राम पंचायत सदस्यों और 571 ग्राम पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत हासिल कर दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। राज्य में भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) ने 19 जिला परिषदों, 85 आंचलिक परिषदों, 1113 ग्राम पंचायत सदस्यों और 119 ग्राम पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत प्राप्त की, जबकि एआईयूडीएफ के 26 जेडपीपी, 103 एपीपी, 402 जीपी सदस्य और 93 जीपी अध्यक्ष चुने गए हैं।

पंचायत चुनावों के दूसरे दिन भाजपा ने 105 में से 63 जिला पंचायतों पर अपनी जीत का परचम लहराया। कांग्रेस को 28 और एजीपी 7 सीटों पर सफलता मिली। 13 दिसंबर तक घोषित परिणामों के अनुसार, भाजपा को 5,095 जिला पंचायत वार्ड, कांग्रेस को 3,690, एजीपी को 931 और एआईयूडीएफ को 483 वार्डों पर जीत हासिल हुई।

वहीं 1,363 ग्राम पंचायत अध्यक्ष पदों के घोषित परिणामों के अनुसार भाजपा को 573, कांग्रेस को 416 और एजीपी को 186, एआईयूडीएफ को 63 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 117 सीटें प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के विधानसभा क्षेत्र माजुली में सभी चार जिला परिषद सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। भाजपा ने डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सोनितपुर, मोरीगांव, कामरूप और गोलाघाट जिला परिषद पर विजय प्राप्त की। उत्तर बैंक की जिला परिषद पर भी भाजपा को जीत हासिल हुई है। वहीं एजीपी भाजपा के समर्थन से बोंगईगांव जिला परिषद जीतने में सफल रही है।

जीत के बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने हेंगबाड़ी स्थित अपने राज्य मुख्यालय पर 'विजय उत्सव' मनाया। ■

सत्य की जीत हुई : अमित शाह

भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को अहम फैसला सुनाया। सीजेआई श्री रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राफेल सौदे के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस सौदे की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। इसलिए इसकी एसआईटी जांच नहीं होगी। सीजेआई ने कहा कि राफेल सौदे में कोई धांधली या अनियमितता नहीं है। राफेल विमान की गुणवत्ता पर कोई शक नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 14 दिसंबर को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कुछ ज्वलंत प्रश्न पूछे।

श्री शाह ने देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने और जनता को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी को देश की जनता और सेना के जवानों से माफी मांगनी चाहिए।

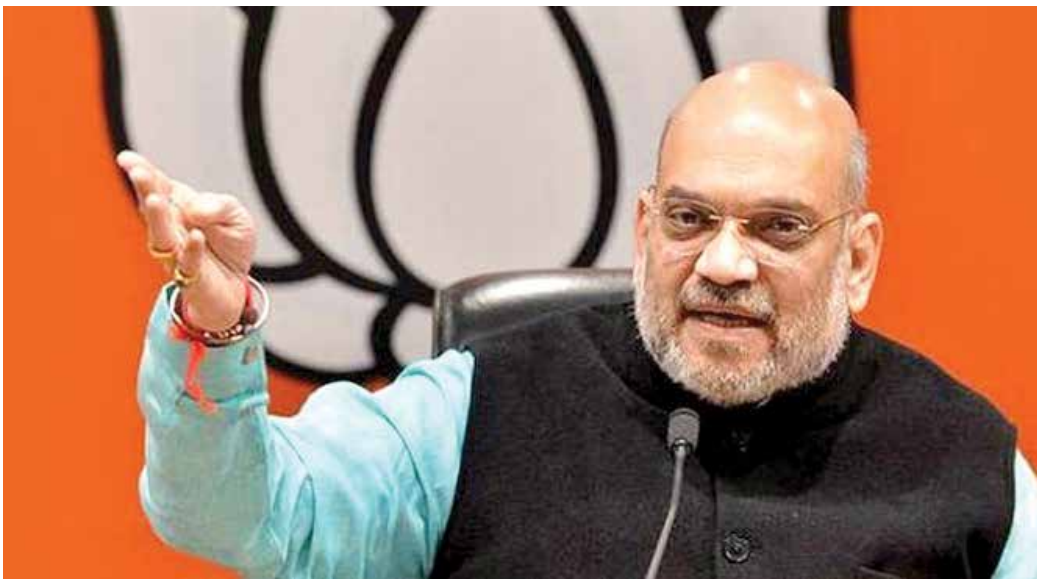

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं आज देश की जनता की ओर से राहुल गांधी से चार सवाल पूछना चाहता हूं। उन्हें इन चारों सवालों का जवाब देश की जनता को देना चाहिए।

पहला – राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर जितना झूठ देश की जनता के सामने कहा, उसका सोर्स ऑफ़ इन्फॉर्मेशन क्या था? राहुल गांधी को अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए देश को बताना चाहिए कि कौन उन्हें ये झूठी सूचनाएं देता था जिसके आधार पर राहुल गांधी ये आरोप लगाते थे? देश की जनता राहुल गांधी से उनका सोर्स ऑफ़ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है।

दूसरा – 2001 में भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट बताई थी। 2007 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने डील की प्रक्रिया को फाइनल करने की शुरुआत की, तो फिर 2007 से 2014 तक राफेल डील क्यों सोनिया-मनमोहन सरकार फाइनल नहीं कर पाई? क्या इसमें कमीशन का अमाउंट तय होना बाकी था या फिर दलालों की भूमिका निर्धारित करनी थी?

तीसरा – कांग्रेस ने जितने भी सौदे किये, सब में दलालों की भूमिका रखी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जिसमें बिचौलियों का कोई सवाल नहीं उठता। कांग्रेस की सरकार में कभी क्वात्रोच्चि तो कभी मिशेल को दलाली का मौक़ा मिल जाता था। देश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकारों ने अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को क्यों नहीं माना?

चौथा – 2007 से 2014 तक देश की रक्षा जरूरतों से संबंधित सभी मामलों को लटका कर कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने क्यों देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया? एयरक्राफ्ट लेट होने का जिम्मेदार कौन है, राहुल गांधी को इसे देश की जनता को बताना चाहिए। ■

जीएसटी परिषद द्वारा नववर्ष का बड़ा तोहफा

टीवी, सिनेमा टिकट सस्ता

जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की। परिषद ने जीएसटी की 28 प्रतिशत की सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से सात को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया है। इसके साथ ही 28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं। कर दर में संशोधन का यह निर्णय आगामी नव-वर्ष के दिन से प्रभावी होगा। परिषद की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इन फैसलों की घोषणा की ।

श्री अरुण जेटली ने कहा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने से सालाना राजस्व में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा, ''जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है।" उन्होंने कहा, "28 प्रतिशत की दर का धीरे-धीरे पटाक्षेप हो जाएगा...अगला लक्ष्य परिस्थिति अनुकूल होने के साथ सीमेंट पर जीएसटी में कमी करना है।" अब 28 प्रतिशत की कर दर वाहनों के कल-पुर्जों और सीमेंट के अलावा केवल विलासिता के सामान और अहितकर वस्तुओं पर ही रह गया।

वित्त मंत्री ने बताया कि सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकटों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की दर से और 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी लगेगा। इसी तरह 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन पर अब 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

प्रमुख वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी

क) 28% से 18%

- 32 इंच तक के आकार के टीवी और मॉनिटर
- नए रबर चढ़े टायर या रबर के वायवीय टायर
- लिथियम आयन बैटरियों के पावर बैंक। लिथियम आयन बैटरियां पहले ही 18 प्रतिशत में हैं। इससे लिथियम आयन बैटरी और पावर बैंक की दरों में समानता आएगी।
- डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर
- वीडियो गेम कंसोल और एचएस कोड 9504 के दायरे में आने वाले अन्य गेम्स और खेल आवश्यकताएं
- घिरनियां, ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक, गियर बॉक्स वगैरह

ख) 28% से 5%

- दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन के पुर्जे और सामान

अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी

क) 18% से 12%

- रफ तरीके से चौकोर किया या हटाया हुआ कॉर्क
- प्राकृतिक कॉर्क की सामग्री
- समुच्चयित कॉर्क

ख) 18% से 5%

- संगमरमर का मलबा

ग) 12% से 5%

- प्राकृतिक कॉर्क
- सैर की छड़ी
- फ्लाई एश से बनी ईंटें

घ) 12% से शून्य

- संगीत पुस्तकें

ड.) 5% से शून्य

- सब्जियां (कच्ची अथवा भाप या उबलते पानी में पकी), जमी हुई, ब्रांड वाली और यूनिट कंटेनर में रखी गईं
- सब्जी जो अस्थायी रूप से संरक्षित की गई हों (जैसे सल्फर डाईऑक्साइड गैस में, नमक के पानी में, सल्फर के पानी में या दूसरे परिरक्षक सॉल्यूशन में), लेकिन तुरंत उपभोग के लिए उस अवस्था में अनुपयुक्त हो।

विविध

- स्वर्ण आभूषणों के सामान के निर्यातकों को नामित एजेंसियों द्वारा सोने की आपूर्ति को जीएसटी से छूट।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या

नौकरशाहों को मिले तोहफों की नीलामी से सरकार को मिली प्राप्तियों को जीएसटी से छूट, प्राप्तियां, जिनका उपयोग सार्वजनिक या परोपकारी कार्य के लिए किया जाता है।

- निजी सड़क वाहनों के अस्थायी आयात पर सीमा शुल्क आचार के अंतर्गत अस्थायी उद्देश्य के लिए आयात किए वाहनों को आईजीएसटी/मुआवजा उप-कर से छूट।
- जूते के लेन-देन मूल्य के आधार पर 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत की दर लागू की जाएगी।
- मौजूदा 5 प्रतिशत/12 प्रतिशत वाले फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी) पर मूल्य अनुसार 12 प्रतिशत समान जीएसटी दर लागू।

सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र या अन्य अक्षय ऊर्जा संयंत्रों पर जीएसटी

- अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके उत्पादन के लिए हिस्सों पर (बायो गैस संयंत्र/सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, सौर ऊर्जा उत्पादक व्यवस्था वगैरह) जीएसटी की 5 प्रतिशत दर निर्धारित की गई है, जो इस दर के अध्याय 84, 85 या 94 के अंतर्गत आती हो। इन संयंत्रों में उपयोग होने वाली अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर उपयुक्त जीएसटी दर लागू होगी।

जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय

- प्रत्येक कर शीर्ष के लिए एक एकल नकद बहीखाता होगा। जीएसटीएन और लेखा परीक्षकों के परामर्श से कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- केंद्र या राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत रिफंड राशि के संवितरण के लिए एकल प्राधिकरण की एक योजना पायलट आधार पर लागू की जाएगी। शीघ्र ही इसके लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 01.04.2019 से परीक्षण के आधार पर और 01.07.2019 से अनिवार्य आधार पर पेश किया जाएगा।
- फार्म जीएसटीआर-9, फार्म जीएसटीआर-9ए और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9सी में मिलान विवरण के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख 30.06.2019 तक आगे बढ़ायी जाएगी। ■

नवंबर में खुदरा महंगाई डेढ़ साल के निचले स्तर 2.33% पर

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.71 फीसदी और शहरी क्षेत्रों के लिए 3.12 फीसदी रही

खुदरा महंगाई नवंबर में घटकर 2.33 फीसदी पर आ गई। यह पिछले डेढ़ साल का न्यूनतम स्तर है। इससे पहले जून 2017 में खुदरा महंगाई 1.46 फीसदी रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 12 दिसंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 2.33 फीसदी रही। एक साल पहले नवंबर 2017 में यह 4.88 फीसदी थी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 1.71 फीसदी (अनंतिम) रही, जो नवंबर 2017 में 4.79 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर नवंबर, 2018 में 3.12 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी, जो नवंबर 2017 में 4.90 फीसदी थी। ये दरें अक्टूबर, 2018 में क्रमशः 2.82 तथा 4.04 फीसदी (अंतिम) थीं।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने नवंबर, 2018 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर (-) 2.33 फीसदी (अनंतिम) रही, जो नवंबर 2017 में 4.04 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर नवंबर, 2018 में (-) 3.04 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई, जो नवंबर, 2017 में 4.90 फीसदी थी। ये दरें अक्टूबर, 2018 में क्रमशः (-)0.65 तथा (-)1.15 फीसदी (अंतिम) थीं।

अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर नवंबर, 2018 में 2.33 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई है, जो नवंबर 2017 में 4.88 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2018 में 3.38 फीसदी (अंतिम) थी।

इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर नवंबर, 2018 में (-)2.61 फीसदी (अनंतिम) रही है, जो नवंबर, 2017 में 4.35 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2018 में (-)0.86 फीसदी (अंतिम) थी। ■

प्रधानमंत्री ने रायबरेली में विभिन्न विकास परियोजनाएं आरम्भ कीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 दिसंबर को रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्टरी का दौरा किया। उन्होंने 900वें कोच तथा एक हमसफर रेक को झण्डी दिखाई। प्रधानमंत्री ने रायबरेली में विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं को समर्पित किया गया है, उद्घाटन किया गया है या जिनका शिलान्यास किया गया है, उनका संचित मूल्य 1,000 करोड़ रुपए के बराबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉडर्न कोच फैक्टरी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है और यह रायबरेली को रेल कोच विनिर्माण का एक वैश्विक हब बना देगी।

श्री मोदी ने स्मरण किया कि 1971 में आज के ही दिन भारतीय सेना ने आंतक, क्रूरता एवं अराजकता के प्रतीक को हराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक तरफ सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारी सशस्त्र सेना मजबूत हो।

उन्होंने कहा कि जो केवल झूठ ही बोलते हैं वे रक्षा मंत्रालय, वायुसेना एवं यहां तक कि एक विदेशी सरकार पर भी आशंकाएं जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की प्रवृति पर केवल सच्चाई द्वारा ही विजय पायी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश की सुरक्षा एवं सशस्त्र बलों की आवश्यकता का सवाल आता है तो केन्द्र सरकार केवल राष्ट्र के हित को ही ध्यान में रखती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने पहले ही 22 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। इसी निर्णय से किसानों को 60 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी उन किसानों को लाभ पहुंचा है, जिनकी फसलें आकस्मिक कारणों से नष्ट हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र के प्रति वचनबद्ध है। ■

प्रधानमंत्री द्वारा प्रयागराज में नए हवाई अड्डा परिसर का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 दिसंबर को प्रयागराज में एक नए हवाई अड्डा परिसर और कुंभ मेले के लिए समेकित कमान एवं नियंत्रण केन्द्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गंगा पूजन किया तथा स्वच्छ कुंभ प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने प्रयागराज में अक्षय वट का दौरा किया। उन्होंने प्रयागराज के अंडावा में भी विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित किया, उनका उद्घाटन किया या शिलान्यास किया।

एक विशाल जनसमूह को संबंधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि इस बार अर्द्ध कुंभ के तीर्थयात्री अक्षय वट की यात्रा करने में भी सक्षम हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयागराज के लिए अच्छा संपर्क सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को आज समर्पित किया गया वे बुनियादी ढ़ांचे एवं संपर्क दोनों की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि नये हवाई अड्डा टर्मिनल का निर्माण एक वर्ष के रिकार्ड समय में पूरा कर लिया गया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्द्ध कुंभ आने वाले भक्तों के लिए एक अनूठा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के गौरवशाली अतीत और गतिशील भविष्य को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वच्छ गंगा सुनिश्चित करने पर भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीवेज उपचार संयंत्र एवं घाटों के सौन्दर्यीकरण की बड़ी भूमिका होगी।

प्रधानमंत्री ने कुंभ की भारत एवं भारतीयता के एक प्रतीक के रूप में व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह हमें एकजुट करता है और एक भारत, स्वच्छ भारत की झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि कुंभ का आयोजन केवल विश्वास की बात नहीं है, बल्कि यह सम्मान की भी बात है और कुंभ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अच्छी तरह ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्द्ध कुंभ प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार 'नवीन भारत' विरासत एवं आधुनिकता दोनों को समावेशित करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश को सावधान करना चाहते हैं कि कुछ तत्व न्यायपालिका पर अनुचित दबाव बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व अपने को सभी प्रकार के संस्थानों से ऊपर समझते हैं। ■

राष्ट्र के वैभव में व्यक्ति का वैभव

(12 जून, 1959 को संघ शिक्षा वर्ग, दिल्ली में दिए गए बौद्धिक का अंतिम भाग)

दीनदयाल उपाध्याय

कुटुंबों में झगड़े कब शुरू होते हैं? जब छोटा भाई सोचता है कि मैं ही सेवा करता हूं, बड़ा भाई तो करता ही नहीं। इसी तरह बड़ा भाई सोचता है कि मैं ही सारी व्यवस्था करता हूं। लेकिन अच्छे परिवारों में ऐसा नहीं होता। दोनों भाइयों को अपना कर्तव्य करना होता है। इसी प्रकार गुरु-शिष्य का संबंध रहता है। थोड़ी भी गुरु ने आदर की अपेक्षा की कि संबंध टूटा। इसी प्रकार पति-पत्नी का भी संबंध रहता है। इस दृष्टि से भी अपेक्षा का भाव आधार नहीं बनाया गया। कर्तव्य के नाते ही सभी काम करते हैं। कर्तव्य में प्रतिदान की भावना नहीं रहती। यहां जैसे को तैसा नहीं चलता। बहन, भाई, पिता, पुत्र, पत्नी, पति-सभी कर्तव्य-बुद्धि लेकर चलते हैं।

शाखा में भी स्वयंसेवक इसी कर्तव्य भाव को लेकर चलता है। मुख्य शिक्षक कहे कि दस विसलें लगाता हूं, फिर भी स्वयंसेवक ध्यान नहीं देते। लो, यह विसल पड़ी है। ऐसा यहां नहीं होता। न ही स्वयंसेवक यह सोचता है कि अभी तो सोया हूं, इसलिए नहीं जाऊंगा। अधिकार की कल्पना का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। यहां न तो कार्यवाह कभी इस्तीफ़ा देता है, न स्वयंसेवक ही। जितना हम कर्तव्य भाव से चलते जाएंगे, तो जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे, वे भी कल को वैसा ही करने लग जाएंगे।

कर्तव्य यानी हमारा मूक भाव है। इन गुणों के साथ-साथ एक और विशेषता जो जुड़ी है, वह है त्यागशक्ति की। हम अपने हर कार्य की रचना इसके आधार पर ही करते हैं। स्वयंसेवक शाखा में आता है तो वह घर की कुछ बातों को ध्यान से निकालकर आता है। कभी घर वालों के सिनेमा जाने के आग्रह को टालता है। यह ठीक है कि यह त्याग है, लेकिन इसे त्याग की संज्ञा देना भी शायद कठिन हो। रोज़ की शाखा के लिए चाहे छोटा ही क्यों न हो, त्याग करना पड़ता है। एक बार विस्तारक योजना में एक कार्यकर्ता एक स्थान पर गए। वहां पर उसने प्रशिक्षण वर्ग के लिए बातचीत की तो तीनचार लोग तैयार हो गए। मैं भी एक दिन वहां जा पहुंचा। विस्तारक महोदय से पूछा कि क्या हाल है? कहने लगा कि प्रशिक्षण के लिए चार लोग तैयार हैं। अच्छा, जरा उन्हें मिलाओ तो सही। वह उन्हें ले आया। पूछने पर कहने लगे कि हां साहब, वर्ग के लिए तैयार हैं। उनसे खुलकर बात की तो वे कहने लगे कि हम उस कैंप में गए थे तो यह मिला था, वह मिला था। मैंने उन्हें बताया कि भई, यहां तो ऐसा नहीं होता है। यहां तो छोटी-से-छोटी बात का त्याग करना पड़ता है। तन, मन और धन-किसी को भी अर्पण करने को तैयार रहना पड़ता है।

गुरु-दक्षिणा करते समय भी यही भाव रहता है कि मुझे अधिक-से-अधिक अर्पण करना है। यहां न तो ख्याति की इच्छा ही रहती है और न ही नाम घोषित होते हैं। संपूर्ण संस्कृति का त्याग के आधार पर निर्माण किया है। पश्चिम की संस्कृति भोग के आधार पर खड़ी हुई है। यहां तो अधिक-से-अधिक त्याग जो करता है, वही बड़ा माना जाता है। उसी के आगे सभी नत-मस्तक होते हैं। संन्यासी को केवल इसी कारण सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। शाखा के कार्यक्रमों के द्वारा ये सारे गुण आने लगते हैं।

त्याग का स्वाभाविक परिणाम संयम है। साथ ही तपस्या का गुण निर्माण हो जाता है। अपने सामने जो आदर्श रखा है, उसे पूरा करने के लिए हम निरंतर जुटे रहते हैं। हम कहते हैं कि हम संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। संरक्षण का अर्थ यह नहीं कि संस्कृति नाम की कोई वस्तु किसी कमरे में पड़ी है और हम उस कमरे के चारों ओर रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। संस्कृति की रक्षा का मतलब यह है इस संस्कृति की जो-जो विशेषताएं हैं, यदि वे अपने जीवन में आती गईं तो कहेंगे कि संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। केवल संस्कृति का ज्ञान देनेवाली कुछ किताबों को छापने, विवरण आदि सुरक्षित रखने से संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। वह कोई संस्कृति की रक्षा का काम थोड़े ही कहा जाएगा।

ऐसी कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती कि जिसका कारण इसके विनाश का भय है, परंतु यदि इसके आधार पर जीवन बिताने वाले ज्यादा-से-ज्यादा लोग निकलते हैं तो फिर संस्कृति प्रतिष्ठित है, यह कहा जाएगा। स्वार्थ के आधार पर, व्यापार बुद्धि से कार्य करनेवाले भी दिखाई देते हैं। व्यापार के माध्यम से वेदों की व्याख्या करना, उन्हें पढ़ाना आदि संस्कृति की रक्षा किस प्रकार कह सकते हैं? वह तो बाहरी अभिव्यक्ति मात्र होगी। ऋषियों से प्राप्त आदर्श जब जीवन में प्रकट होंगे, तब संस्कृति की रक्षा होगी। जिन बातों से यह आदर्श जीवन में प्रकट हो सके, ऐसी समाज व्यवस्था की गई। संपूर्ण समाज के प्रति आत्मीयता का भाव, धर्म के प्रति निष्ठा का भाव और त्यागमय जीवन यह हमारे व्यवहार को कसौटी पर कसते हैं। यदि इन जीवन मूल्यों के प्रति अपने जीवन द्वारा श्रद्धा दिखाई और लोगों को लगने लगता है कि यह श्रेष्ठ जीवन है, तब समझो कि संस्कृति का संरक्षण करते हैं।

जहां-जहां हम शाखा लगा देते हैं, वहां-वहां यह भाव खड़ा हो जाता है। चाहे शिशु ही क्यों न हो, सबमें निस्वार्थ भाव से, त्याग

भाव से, घर की चिंता न करते हुए राष्ट्र का कार्य करने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। यह बस आत्मिक प्रेम के आधार पर सहज संभव हो पाता है। एक व्यक्ति ने कहा, यह तो आपका स्वयंसेवक है। इसलिए इस झगड़े में तो आप उसका पक्ष ही लेंगे। कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसी बात नहीं। बात सुनकर जो ठीक लगेगी, वही कहा जाएगा। पर वह माना नहीं। इस पर कहा गया कि भई, संघ के दरवाजे तो हरेक के लिए खुले हैं। आप भी आएं, तो फिर आपका पक्ष भी शायद लिया जाए। ऐसी लाखों लोगों की धारणा बनी है, स्वयंसेवकों के प्रेम के बारे में।

ऐसा व्यक्ति का संस्कार तो करना ही है, लेकिन इसके साथ ही सामूहिक जीवन की सृष्टि भी करनी पड़ती है। जो गुण एक स्वयंसेवक में रहते हैं, वही गुण व आदर्श कुटुंब में पैदा होंगे। वहां कुटुंब भाव बराबर छाया रहता है। फिर एक कुटुंब, दूसरा कुटुंब इस प्रकार जो सब कुटुबों को मिला या वह उससे ऊपर राष्ट्र का भाव था, वह पोषित होना बंद हो गया। कुटुंब भाव तक ही विचार सीमित हो गया। पहले कुटुंबों ने एक सीढ़ी का रूप धारण किया था। उसके द्वारा ही ऐसे संस्कार मिलते थे कि व्यक्ति, राष्ट्र एवं समाज के लिए निस्स्वार्थ भाव से काम करे, लेकिन जब वही बाधक बन गया तो फिर कुटुंब का सहारा छोड़कर नई पद्धति से राष्ट्रभक्ति उत्पन्न करने का कार्य शुरू किया गया। एकता का भाव जाग्रत् करने का प्रयास किया। प्राचीन काल में वेदों और विविध स्मृतियों ने आदर्शों के आधार पर आचार-धर्म को जन्म दिया। वहां पर हमारे पूर्वजों ने सारे देश में एकता के लिए भी संस्कार दिए। यहां जो समाज के सामने तीर्थों की कल्पना, प्रातः स्मरण और सब आदर्श महापुरुष, जिनके जीवन ने भूमि के एक-एक कण से तादात्म्य स्थापित कर लिया था—इन सबका स्मरण इस एकता को जगाने के लिए ही किया जाता है।

लेकिन धीरे-धीरे कालांतर में ऊपर की चीजें तो रह गईं, पर अंदर का भाव क्षीण हो गया। जैसे कुंभ होते थे। यह एक प्रकार से अखिल भारतीय सम्मेलन होते थे, जिनमें धर्म एवं समाज के गहन प्रश्नों पर चर्चा होती थी। सारे समाज की दृष्टि से जो विचार चाहिए, उसको पोषण मिलता था। कालांतर में व्यक्ति यही सोचकर कुंभों में जाने लगे कि इससे मोक्ष मिलेगा। एक डुबकी लगाकर पाप धुल जाएंगे। भारत की एकता की कल्पना ही इसमें से निकल गई। सबकी तीर्थ यात्रा में यहां व्यक्तिगत मोक्ष ही आधार बन गया। यह जो राष्ट्र की एकता की भावना कमज़ोर पड़ गई, उसे नए ढंग से खड़ा करने, सद्भावना को जाग्रत् करके हिंदू के नाते अपना यह संस्कार का कार्य चलता है। यह एक व्यवस्था निर्माण करने, अनुशासन लाने का कार्य है, क्योंकि यदि कहे गए सारे गुण रहे और यह व्यवस्था और अनुशासन न रहा तो फिर यह गुण छोटे-छोटे समूहों के। लिए ही रह जाएंगे। कुछ नए आधार देकर इस भावना को पुष्ट कर सकें, इसके लिए ही संघ का निर्माण हुआ है।

प्राचीन काल में वेदों और विविध स्मृतियों ने आदर्शों के आधार पर आचार-धर्म को जन्म दिया। वहां पर हमारे पूर्वजों ने सारे देश में एकता के लिए भी संस्कार दिए। यहां जो समाज के सामने तीर्थों की कल्पना, प्रातः स्मरण और सब आदर्श महापुरुष, जिनके जीवन ने भूमि के एक-एक कण से तादात्म्य स्थापित कर लिया था—इन सबका स्मरण इस एकता को जगाने के लिए ही किया जाता है।

एक और विचार भी आता है कि राष्ट्र का विचार तो किया गया, लेकिन मानवमात्र का विचार तो किया ही नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम इस पर सत्य के आधार पर विचार करेंगे। यह जो मानव है-यह अनेक राष्ट्रों का समूह ही है। यह जो राष्ट्र है, इसकी ऐसी हस्ती है कि लोग चाहे मिट जाएं, पर इसकी हस्ती नहीं मिट सकती। पहले भी नहीं मिट पाई। हम विश्व का विचार राष्ट्र कार्य करते हुए करेंगे, तो आगे बढ़ सकेंगे। राष्ट्र के बिना मानवमात्र का विचार किया तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि सब मानवों को बांधनेवाला रस्सा कौन सा है? और तो कोई सूत्र दिखाई नहीं देता। हां, नाक, कान, आंख, टांगें और अन्य इंद्रियां, जैसे बुद्धि एक समान हैं। बाक़ी तो विभेद ही विभेद हैं। भाषाएं अनेक, अच्छे-बुरे की कल्पनाएं अनेक और गुण अनेक हो गए हैं। कई लोगों ने मानव के मोटे-माटे रूप को देखकर ही, मानव समूहों की विशेषताओं को न देखकर केवल नाक, मुंह, इंद्रियों की समानता के आधार पर मानव को एक करने की कोशिश की।

इसलाम और ईसाइयत ने यहां तक कहा कि सब मानव एक हैं और फिर कुछ मोटे-मोटे उसूल रख दिए। परंतु हमने देखा कि यह सब चल नहीं पाया। इन्हें राष्ट्रीयता की चट्टान से टक्कर लगी और ये चूर-चूर हो गए। अनेक राष्ट्र ऐसे हैं, जो क्रिश्चियन हैं, लेकिन वे भी आपस में लड़े। ईसाइयत के आधार पर लड़ाई टाली नहीं जा सकी। उसके फेल होने का कारण क्या, तो उसने सबको Flat बनाने की कोशिश की। इंग्लैंड ने पहले रोम से संबंध तोड़ा, फिर अपना अलग चर्च स्थापित किया। पश्चिम में गिरजाघर में लोग साप्ताहिक एकत्र होते हैं। वह भी इसलिए कि वह पारस्परिक संपर्कों के लिए एक अच्छा स्थान है। उनका एक और उपयोग अवश्य बाक़ी रह गया है कि अपने राष्ट्र के स्वार्थ के लिए हथियार बनाकर पादरियों द्वारा अन्य देशों को क़ाबू में करने के लिए, इन्हें अपने प्रभुत्व में लाने के लिए, जो भी ईसाई मिशनरी जिस देश में जाता है, वह दूसरे देश में जाकर ईसाइयत का प्रचार नहीं करता, वह तो अपने देश की सभ्यता का प्रचार करता है।

गोवा हमारे देश में है। लेकिन वहां का रहन-सहन, दैनिक जीवन, मकान आदि देखने से पता चलता है कि पुर्तगाल के किसी

हिस्से में हम घूम रहे हैं। पांडिचेरी में फ्रांस का तथा बाक़ी हिस्से में जहां ईसाइयों ने धर्म-परिवर्तन किया, अंग्रेज़ी सभ्यता का ही बोलबाला है। वास्तव में मिशनों की स्थापना से विभिन्न देशों द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने ही देश में जो पाकिस्तान नाम का देश बना, वह इसलाम के नाम पर लोगों को भड़काकर स्थापित किया गया, परंतु वही पाकिस्तान अफगानिस्तान से दुश्मनी लेता है। ईरान में क्या हुआ? रजा शाह पहलवी ने अपनी पहलवी भाषा को स्थान दिया। अरबी भाषा को एकदम हटा दिया और यह सब राष्ट्र के अभिमान के कारण ही हुआ। टर्की जो कि इसलाम का केंद्र माना जाता था, वहां पर भी जब राष्ट्रवाद प्रबल हुआ तो कमाल पाशा ने स्वयं खलीफा को, जिसके प्रथम महायुद्ध के पश्चात् हटाए जाने पर सारे इसलाम जगत् में हाहाकार मच गया था। भारत में तो मुसलमानों को सहायता देकर ख़िलाफ़त आंदोलन भी खड़ा हुआ था, एकदम हटा दिया। अरबी भाषा को देश निकाला देकर तुर्की भाषा की प्रतिष्ठा की, यहां तक कि अपना नाम भी कमाल अली से कमाल पाशा कर दिया।

वास्तव में जहां राष्ट्र भाव दुर्बल था, वहां इसलाम फैल गया, ईसाइयत फैल गई। लेकिन जहां यह भाव मजबूत रहा, वहां यह नहीं जम पाया। इस तथ्य को उर्दू के प्रसिद्ध कवि इकबाल ने अपनी कविता में स्वीकार किया। जहां जितनी राष्ट्रीयता दुर्बल थी, वहां उतना नुक़सान हुआ।

इसी प्रकार का एक प्रयास कम्युनिज्म करना चाहता है। वह भी दुनिया भर के लोगों को एक करना चाहता है। उसकी भी यदि टक्कर आ रही है तो राष्ट्रीयता से। कम्युनिज्म का मंत्र सृष्टा मार्क्स माना जाता है। उसने भविष्यवाणी की थी कि जहां औद्योगिक उन्नति बढ़ती जाएगी, वहां धन की विषमता बढ़ने के कारण से पहले क्रांति होगी और मजदूरों को राज्य स्थापित होगा। यूरोप में औद्योगिक क्रांति सबसे अधिक इंग्लैंड में हुई, परंतु वहां कम्युनिज्म का नामोनिशान नहीं, फिर इस आधार पर क्रांति हुई कहां? तो रूस में जो औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ था, वहां भी यह कब संभव हुआ, जब वहां राष्ट्रीयता निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी, रूस जर्मनी से हार खा चुका था। फ़ौजें निराश थीं, देश आत्मविश्वास खो चुका था। तब लेनिन क्रांति करने में सफल हुआ और वह भी कैसर के हाथ में कठपुतली बनकर। यानी जैसे सूर्य डूबता है। तो कीड़े निकलकर आते हैं। सूर्य निकला तो कीड़े भाग खड़े होते हैं, वैसे ही राष्ट्रीयता जागी तो ही टीटो टक्कर लेने के लिए खड़ा हो गया। आज हम देखते हैं कि कम्युनिज्म की स्थिति शायद उतनी प्रबल और स्थिर नहीं, जितनी आज से दस वर्ष पूर्व थी। इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कम्युनिज्म भी मानव को एक करने की बजाय रूस का साम्राज्य बढ़ाने का साधन मात्र बनकर रह गया है।

हम यदि मानव की एकता ला सकते है तो इस प्रकार निर्मित समूहों की विशेषताओं को साथ लेकर चलने से। तभी मानव की कुछ सेवा हो सकती है। दुनिया का कोई भी महापुरुष शून्य में बैठकर विचार नहीं करता। उसकी अपनी परिस्थितियां होती है-इर्दगिर्द रहनेवाले विशेष प्रकृति के लोग होते हैं। उनके अनुसार उसके कार्य की रूपरेखा बनती है, लेकिन यदि मार्क्स ने जिस परिस्थिति में जन्म लेकर उसके संबंध की विचारधारा खड़ी की, इस क्षेत्र के अतिरिक्त यदि उसने कहा कि सारी दुनिया को इस प्रकार बनाना होगा तो वास्तव में वह अपनी चीज़ लादना चाहता है। जहां इतनी अनेकता, विभिन्नता उत्पन्न हो चुकी है, वहां उन सब विशेषताओं को ख़त्म करके चलना संभव नहीं। चाहिए तो यह कि प्रत्येक समूह अपनी-अपनी विशेषताएं लेकर खड़ा हो और विचार करे कि दुनिया को हम यह योगदान करेंगे। हमें जो स्वर मिले हैं, उन्हीं के द्वारा सुंदर गा सकेंगे। इसी के आधार पर हम विचार करें, सोचें कि किस प्रकार अपनी संस्कृति को अपनाकर संसार को कुछ विशेषता दे सकते हैं।

पहले हिंदुस्तान के बारे में सोचें, बाद में जो कुछ ज्ञान हमारे पास है, वह दुनिया को दें। दुनिया को अच्छा लगे, तो ग्रहण करे। यह हमारा कोई आग्रह नहीं, ज़ोर जबरदस्ती नहीं। अपनी बात कह दी है। अच्छी लगे तो ले लो। आज तो वैसे भी संसार ऐसी आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। हमारे पास एक श्रेष्ठ समाज रचना है, व्यवस्था है, उसको ठीक प्रकार से उतारने के लिए जो आधारभूत संस्कार चाहिए, वे अपनाएं। उन्हें जीवन में लाकर हम कुछ प्रत्यक्ष व्यवस्था खड़ी कर सकें और संसार की कुछ सेवा कर सकें, बस इतना ही अपने कार्य का रूप है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह हमें इसको पूरा करने की सामर्थ्य दे। ■

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी

(25 दिसंबर 1924 – 16 अगस्त 2018)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक शिखर पुरुष थे। वे एक कुशल राजनेता, प्रशासक, कवि व पत्रकार भी थे। उन्होंने राजनीति को दलगत और स्वार्थ की वैचारिकता से अलग हट कर अपनाया और जिया भी। राजनीति में धुर विरोधी भी उनकी विचारधारा और कार्यशैली के कायल रहे। उन्होंने पोखरण जैसा आणविक परीक्षण कर दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका के साथ दूसरे मुल्कों को भी भारत की शक्ति का अहसास कराया।

अटलजी ने 21वीं सदी के मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत की आधारशिला रखी। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी दूरगामी नीतियों ने भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श किया। अटलजी की जीवटता और संघर्ष के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तरोत्तर विकास हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संदेश को प्रसारित करने के लिए देश भर की यात्रा की।

अटलजी का कविताओं से बड़ा प्रेम था। कविताओं को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरी कविता जंग का एलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य-निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जयघोष है। उनकी कविताओं का संकलन 'मेरी इक्यावन कविताएं' खूब चर्चित रहा जिसमें..हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा...खास चर्चा में रही।

अटल बिहारी वाजपेयी: संक्षिप्त परिचय

- 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर में जन्म।
- 1957 में पहली बार लोकसभा पहुंचे।
- सर्वाधिक समय तक गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहने वाले एकमात्र राजनेता।
- भारत और पाकिस्तान के बीच कटु संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। 1999 में लाहौर बस यात्रा की।
- 1996 में पहली बार, 1998 में दूसरी बार, 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
- 1998 में पोखरण परीक्षण करके दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया और विश्व को भारत की परमाणु क्षमता का अहसास कराया।
- भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित।

सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए विचारधारा की राजनीति करने वाले श्री वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने तीन बार 1996, 1998-99 और 1999-2004 में प्रधानमंत्री के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त, 2018 को श्री वाजपेयी का निधन हो गया।

जीवन परिचय

श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित शिंदे की छावनी में हुआ था। अटलजी के पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और मां का नाम श्रीमती कृष्णा वाजपेयी था। अटलजी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। वे 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। श्री वाजपेयी 10 बार लोक सभा के सांसद रहे। वहीं वे दो बार 1962 और 1986 में राज्यसभा के सांसद भी रहे।

सन् 1957 से 1977 तक वे लगातार बीस वर्षों तक जन संघ के संसदीय दल के नेता रहे। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया। आपातकाल के बाद देश की जनता द्वारा चुनी गयी मोरारजी देसाई की सरकार में वे विदेश मंत्री बने। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और वे इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे सुखद क्षण बताते हैं।

राष्ट्र निर्माता अटलजी

देश की प्रगति के लिए अटलजी ने 'स्वर्णिम चतुर्भुज' योजना का आरम्भ किया। इसके अंतर्गत उन्होंने देश के महत्त्वपूर्ण शहरों को लम्बी-चौड़ी सड़कों से जोड़ा। इससे जहां आम व्यक्ति की यात्रा सुविधाजनक हुई, वहीं व्यापारिक और क़ारोबारी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला। यही नहीं, अटलजी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में सदैव पहल की।

अटलजी ने विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ देश का भविष्य जोड़ा। उन्होंने परमाणु शक्ति को देश के लिए आवश्यक मानते हुए 11 मई 1998 को पोखरन में पांच परमाणु परीक्षण किए। परमाणु परीक्षण के कारण अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अटलजी ने प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए भारत को स्वावलम्बी राष्ट्र बनाने की दिशा में अनथक कार्य किया। ■

समय की मांग है सहमति की राजनीति

एम वेंकैया नायडू

आज जब हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और देश की महान विभूतियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि सुशासन, उत्तरदायी शासन विशेषकर दुर्बल वर्गों के लिए सुगम प्रशासन सदैव अटल जी की प्राथमिकता रही। निःसंदेह वह एक बहुआयामी व्यक्ति थे। एक सहृदय कवि, ओजस्वी वक्ता, करिश्माई राजनेता और इन सबसे बढ़कर एक सौम्य संवेदनशील मानवतावादी। गरीबों और किसानों की समस्याओं के प्रति उनके विशेष आग्रह थे। इस अवसर पर एक उदाहरण स्मरण हो आता है कि किस प्रकार उन्होंने मुझे ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि कैबिनेट के कुछ सहयोगी मंत्रियों का मत था कि ग्रामीण संपर्क सड़कें मूलतः ग्राम पंचायतों के अधीन हैं, लिहाजा संबंधित राज्य सरकारें इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराएं। ऐसे विरोध को दरकिनार करते हुए अटल जी ने मुझे उस योजना को कार्यान्वित करने की इजाजत दी, जो आज भी ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। सिर्फ ग्रामीण संपर्क ही क्यों, अटल जी की सुशासन की अवधारणा में प्रत्येक क्षेत्र में संपर्क साधनों का विस्तार सम्मिलित था, फिर चाहे वह संचार क्रांति हो या राष्ट्रीय राजमार्ग। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सुशासन के ढांचे की नींव है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को ठोस आधार देता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत चार मेट्रो शहरों को राजमार्गों से जोड़ा गया जिससे यात्री और माल यातायात त्वरित और सुगम हो सका।

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया। अटल जी के शासन काल में ही तीन नए राज्यों का निर्माण भी हुआ। आखिर सुशासन है क्या? इसके कई आयाम में सबसे महत्वपूर्ण है जनकल्याण को प्रशासन की हर नीति और कार्यक्रम के केंद्र में रखना। सुशासन की यह अवधारणा भारत के लिए कोई नई नहीं है। सुशासन के विभिन्न लक्षणों, विशेषकर राजधर्म की अवधारणा का उल्लेख भारतीय परंपरा के महान ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रामराज्य का उल्लेख किया है जो सुशासन का आदर्श है जहां भेदभाव से परे सभी एक समान हैं। प्रशासनिक निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, कानून का राज, समानता, समन्वयवादी और कार्यकुशलता-ये सुशासन के मूल तत्व हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया, निष्पक्ष कार्यपालिका सुशासन के स्तंभ हैं। आज के डिजिटल युग में प्रशासन को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाने के लिए हमें उन पुराने दकियानूसी नियमों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं को त्यागना होगा जो निर्णय प्रक्रिया को बेवजह जटिल बनाती हैं अथवा सुविधासंपन्न यथास्थितिवादी अभिजात्य वर्ग के पक्ष में खड़ी प्रतीत होती हैं, विकास प्रक्रिया को बाधित करती हैं और प्रशासन एवं आम नागरिक के बीच विभाजन की एक कृत्रिम दीवार खड़ी करती हैं। मेरा यह मानना है कि जनता को लगना चाहिए कि सरकार द्वारा लिखी जा रही विकास यात्रा में वे भी साझेदार हैं। सरकार के साथ वे भी इस विकास गाथा को लिख रहे हैं।

आज सुशासन प्रदान करने के संकल्प के तहत सरकार ने अनेक कदम उठाए भी हैं। जैसे जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आयुष्मान भारत योजना, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, फसल बीमा योजना, मुद्रा बैंक, अटल पेंशन योजना आदि। इसी क्रम में नोटबंदी काले धन के खतरे, जिसने एक समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर रखी थी, को समाप्त करने की दिशा में एक निर्भीक और दिलेर कदम था। काले धन को समाप्त करने के लिए कई देशों के साथ दोहरा कराधान परिहार संधि जैसे कदम भी उठाए गए।

अटल जी की सुशासन की अवधारणा में प्रत्येक क्षेत्र में संपर्क साधनों का विस्तार सम्मिलित था, फिर चाहे वह संचार क्रांति हो या राष्ट्रीय राजमार्ग। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सुशासन के ढांचे की नींव है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को ठोस आधार देता है। स्वर्णिम चतुष्कोण परियोजना के अंतर्गत चार मेट्रो शहरों को राजमार्गों से जोड़ा गया जिससे यात्री और माल यातायात त्वरित और सुगम हो सका।

भारत पारदर्शिता और जानकारी आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए ओईसीडी देशों के ग्लोबल फोरम का सदस्य भी है। कई देशों ने काले धन पर उपलब्ध वित्तीय जानकारी भारत से साझा करना स्वीकार भी कर लिया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल में भ्रष्टाचार और कालेधन के निवारण तथा अर्थतंत्र में प्रामाणिकता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें देश छोड़कर भागे आर्थिक अपराधियों को

वापस लाने, मुकदमा चलाने तथा बेनामी संपत्ति सहित उनकी अन्य संपत्तियों को जब्त करने जैसे कठोर प्रावधान हैं। हम इसके सकारात्मक परिणाम देख भी रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचार के निवारण की दिशा में उठाया गया हर कदम न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगा, अपितु निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाएगा। भ्रष्टाचार को समाज से निर्मूल करने के लिए आवश्यक है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे संस्कार बचपन से ही दिए जाएं।

विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देशों से 20 से 40 अरब अमेरिकी डॉलर, जो विकास के लिए दी गई कुल सरकारी सहायता का 20 से 40 प्रतिशत है, प्रतिवर्ष उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार के कारण चुराकर विदेशों में जमा कर दी जाती है। भ्रष्टाचार के पहले शिकार गरीब होते हैं। भ्रष्टाचार शासनतंत्र की कार्यक्षमता को क्षीण कर देता है। भ्रष्टाचार ग्रस्त देशों में बाल-मृत्यु दर, कम भ्रष्टाचार वाले देशों के मुकाबले 1/3 अधिक होती है। ऐसे देशों में शिशु मृत्यु दर दोगुनी और छात्रों की स्कूली पढ़ाई छोड़ने की ड्राप आउट दर पांच गुनी अधिक होती है। एक ऐसा परिवेश बनाने की आवश्यकता है जिसमें जागरूक नागरिक, व्हिसिल ब्लोअर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। आज जनधन, आधार और मोबाइल आधारित 'जैम' के साथ धन के सीधे खाते में अंतरण की डीबीटी स्कीम लागू होने से बिचौलियों को प्रायः समाप्त करने में सहायता मिली है। इससे बीच में पैसे की चोरी रुकी है और लक्षित लाभार्थी तक योजना के लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो सका है।

भ्रष्टाचार न सिर्फ अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ईमानदार नागरिकों के विश्वास और निष्ठा को भी डिगाने लगता है। आज भारत विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देश बन रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि जन केंद्रित प्रशासन और सुधारों को तेज कर, विकास की शक्तियों और संपूर्ण सामर्थ्य को उन्मुक्त किया जाए। हम अपने कीमती संसाधनों को बेकार की लोक-लुभावन योजनाओं पर व्यर्थ नहीं कर सकते। समय की मांग है कि सभी दल मिलकर सुधारों, विकास और देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति बनाएं। प्रतिस्पर्धी राजनीति की मजबूरियों को दरकिनार कर अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उदीयमान भारत के लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना आज की प्राथमिकता है। राजनीति और प्रशासन में पारदर्शिता, काले धन और भ्रष्टाचार के दंश का शमन कर सकती है और नागरिकों की सुराज्य की अवधारणा साकार हो सकती है।

अटल जी ने सुधार और विकास के आवेग को मुक्त करने की जो शुरुआत की थी वह बनी रहनी चाहिए। भ्रष्टाचार का मजबूती से दमन किया जाना अपरिहार्य आवश्यकता है। रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म ही उज्ज्वल भविष्य के मार्ग हैं। विश्व की शांति और समृद्धि को विषाक्त करने वाले आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी संगठित रहकर कारगर कदम उठाने होंगे। ■

लेखक भारत के उप-राष्ट्रपति हैं
(दैनिक जागरण से साभार)

अक्टूबर, 2018 में औद्योगिक विकास दर 8.1 प्रतिशत

अक्टूबर, 2018 में औद्योगिक विकास दर 8.1 फीसदी रही। साथ ही, अप्रैल-अक्टूबर, 2018 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.6 फीसदी आंकी गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार अक्टूबर, 2018 में खनन, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर, 2017 के मुकाबले क्रमशः 7.0 फीसदी, 7.9 फीसदी तथा 10.8 फीसदी रही। अप्रैल-अक्टूबर 2018 में इन तीनों क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 3.8, 5.6 तथा 6.8 फीसदी आंकी गई।

विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 21 समूहों ने अक्टूबर, 2017 की तुलना में अक्टूबर, 2018 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की। इस दौरान 'फर्नीचर के विनिर्माण' ने 41.0 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की। काष्ठ और कॉर्क एवं काष्ठ उत्पादों ने 39.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रकाशीय (ऑप्टिकल) उत्पादों की वृद्धि दर 30.2 प्रतिशत आंकी गई। कागज एवं कागज उत्पादों के निर्माण ने (-) 1.8 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।

उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अक्टूबर, 2018 में प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी गुड्स), पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर 2017 की तुलना में क्रमशः 6.0 फीसदी, 16.8 फीसदी, 1.8 फीसदी और 8.7 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर, 2018 में 17.6 फीसदी रही है। वहीं, गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर, 2018 में 7.9 फीसदी रही। ■

अटल जी: एक अनूठे सांसद

लाल कृष्ण आडवाणी

अगर मुझे एक ऐसे व्यक्ति को चयनित करना हो जो अब तक मेरे राजनैतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा हो, जो पचास वर्षों तक पार्टी में मेरा सबसे करीबी सहयोगी रहा हो, और जिसका नेतृत्व मैंने हमेशा बिना किसी दुविधा के स्वीकार किया हो, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी ही होंगे। कई राजनीतिक समीक्षकों ने भी इस बात को माना है कि यह न केवल दुर्लभ है, बल्कि वास्तव में, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में दो राजनीतिक व्यक्तित्वों के लिए एक ही संगठन में साझेदारी की इतनी मजबूत भावना के साथ काम करने का यह एक अद्वितीय उदाहरण है। मैं, अटलजी के साथ अपनी इस राजनीतिक साझेदारी को अपने जीवन का अमूल्य खजाना मानता हूं और मुझे इस पर गर्व है।

अनुभव ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में दीर्घकालिक और अटूट संबंध केवल कुछ साझा उदार लक्ष्यों के प्रति आपसी विश्वास, सम्मान और वचनबद्धता के आधार पर ही संभव हैं। सत्ता के संघर्ष द्वारा संचालित राजनीति की प्रकृति प्रतिस्पर्धी और संघर्ष पर सवार होती है। जबकि एक आम विचारधारा, संस्कारों और आदर्शों द्वारा संचालित राजनीति एक अलग मामला है। जब एक श्रेष्ठ उद्देश्य लोगों के एक समूह को एक साथ लाता है, तो वे छोटे—मोटे मसलों और व्यक्तित्व से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज करना सीखते जाते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, 'अटलजी के साथ आपकी साझेदारी पचास साल तक कैसे रही? क्या आपके और अटल जी के बीच कोई मतभेद या समस्या नहीं रही?

मैं इन सवाल में छुपी पहेली को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को ईमानदारी से कह सकता हूं कि चाहे दशकों से लोग कुछ भी अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अटलजी और मेरे बीच का रिश्ता कभी प्रतिस्पर्धी नहीं रहा, पर मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि हमारे बीच कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। हां, कभी-कभी कुछ मुद्दों पर हमारी राय अलग जरूर रही। हमारा व्यक्तित्व अलग-अलग हैं, और स्वाभाविक रूप से, व्यक्तियों, घटनाओं और मुद्दों पर हमारे विचार कई अवसरों पर भिन्न रहे। यह किसी भी संगठन के लिए सामान्य बात है, जो आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास रखता हो। हालांकि, तीन कारक हमारे रिश्ते की गहराई को परिभाषित करते थे। हम दोनों जनसंघ और फिर भाजपा की विचारधारा से दृढ़ता से जुड़े हुए थे। यह विचारधारा अपने सदस्यों को राष्ट्र पहले, फिर पार्टी,

और स्वयं को अंत में रखने का निर्देश देती थी। हमने उत्पन्न मतभेदों को अपने परस्पर विश्वास और सम्मान को कम करने के लिए कभी अनुमति नहीं दी, लेकिन एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारक भी थाः मैंने हमेशा अटल जी को निस्संदेह और निर्विवाद रूप से अपना नेता स्वीकार किया। हमारे सहयोग के शुरुआती दिनों से ही मैंने हमेशा संगठनात्मक और राजनीतिक मामलों के संबंध में अटल जी द्वारा तय किए गए निर्णयों का अनुपालन किया।

मैं अपने विचार प्रस्तुत करता था, लेकिन एक बार मुझे लगा कि अटल जी चाहते थे कि मैं उनके दृष्टिकोण या वरीयता के साथ जाऊंगा। मेरी प्रतिक्रिया इतनी स्वाभाविक हो गई थी कि कभी-कभी पार्टी में मेरे सहयोगियों या आरएसएस के नेताओं ने अटल जी के फैसलों से असहमत होने की मेरी क्षमता या अनिच्छा पर अपनी नाराजगी व्यक्त भी की। हालांकि, इसने मेरे इस दृढ़ विश्वास में कोई अंतर नहीं आया कि अटल जी को पार्टी संबंधित और बाद में, सरकार से संबंधित मामलों में अंतिम बात कहने का अधिकार है। दोहरा या सामूहिक नेतृत्व एकता के लिए बुरा विकल्प है। मैं अपने सहयोगियों से हमेशा चर्चा करता था कि "कोई भी परिवार बिना मुखिया के एक साथ नहीं रह सकता है, जिसके निर्णय निर्विवाद रूप से परिवार के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाते हो। दीनदयाल जी के बाद अटल जी हमारे परिवार के मुखिया थे।"

यहां मुझे यह भी कहना है कि अटलजी मेरे प्रति एक अनुकूल दृष्टिकोण रखते थे। अगर उनको लगता था कि मेरी सोच एक निश्चित मुद्दे पर क्या है और यदि उस मुद्दे पर कोई गंभीर मतभेद नहीं है, तो वह आसानी से कहते थे कि 'जो आडवाणी जी कहते हैं, वो ठीक है'। इसके बाद चर्चा के तहत मामला का समाधान तुरंत हो जाता था।

एनडीए सरकार के छः वर्षों के दौरान मेरे और अटल जी के बीच एक गैर जरूरी विवाद को बार—बार हवा दी गई, मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह अटकलबाजी कुछ लोगों के लिए यह एक पसंदीदा मुद्दा था। हालांकि, अटल जी ने संसद के भीतर और बाहर इन अटकलों को खारिज कर दिया था। वहीं इंडिया टुडे को दिए गए एक साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि "गृहमंत्री एल.के.आडवाणी के साथ आपके संबंध कैसे हैं? क्या भाजपा दो अलग दिशाओं में जा रही है? तो उनका जवाब स्पष्ट था, उन्होंने कहा 'मैं हर दिन आडवाणी जी से बात करता हूं। हम प्रतिदिन एक दूसरे से परामर्श करते हैं, फिर भी आप अनुमान लगाते हैं। आपका रिकॉर्ड इस बात पर क्यों अटक गया है। एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई समस्या नहीं है। और जब होगी, तो मैं आपको बता दूंगा।"

अपने लगभग छह दशकों के राजनीतिक जीवन में, अटलजी ने अपने विचार से न केवल लोगों को प्रभावित किया है बल्कि उनकी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी, राजनीतिक दूरदर्शिता और रणनीति के कारण सभी राजनीतिक दलों में उनको सम्मान की नजर से देखा जाता रहा। उनके अद्भुत व्याख्यात्मक कौशल ने न केवल संसद में बल्कि सार्वजनिक जीवन के हर मंच पर प्रभाव डाला है। उनकी बुलंद आवाज संसद में हमेशा गूंजती रही। अटल जी समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की राय सुनने में कभी हिचकिचाया नहीं करते थे। उन्होंने जनमानस के कल्याण से संबंधित कई बिल संसद में प्रस्तुत किए।

11 अक्टूबर, 2011 को जन चेतना यात्रा शुरू करने से पहले मैंने अटलजी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद मांगा। मेरी पिछली यात्राओं की तुलना में इस यात्रा में मैंने जो चीज सबसे ज्यादा याद की थी वह थी अटल जी की सक्रिय भागीदारी, जो खराब सेहत की वहज से संभव नहीं थी। लेकिन उनके आशीर्वाद के साथ मैं इस यात्रा पर निकला, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करने और स्विस बैंकों एवं विदेशों में जमा काले धन को वापस लाना था, और हमें इस यात्रा के दौरान पूरे भारत में अभूतपूर्व समर्थन मिला।

अटलजी, मैं और मेरी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार और काले धन के साथ ही समाज में अन्य बुराइयों के खिलाफ रही है। अटलजी द्वारा प्रस्तुत बिलों में एक आम आदमी के कल्याण का दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति दिखाई देती है। ■

तीन कारक हमारे रिश्ते की गहराई को परिभाषित करते थे। हम दोनों जनसंघ और फिर भाजपा की विचारधारा से दृढ़ता से जुड़े हुए थे। यह विचारधारा अपने सदस्यों को राष्ट्र पहले, फिर पार्टी, और स्वयं को अंत में रखने का निर्देश देती थी। हमने उत्पन्न मतभेदों को अपने परस्पर विश्वास और सम्मान को कम करने के लिए कभी अनुमति नहीं दी, लेकिन एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारक भी थाः मैंने हमेशा अटल जी को निस्संदेह और निर्विवाद रूप से अपना नेता स्वीकार किया। हमारे सहयोग के शुरुआती दिनों से ही मैंने हमेशा संगठनात्मक और राजनीतिक मामलों के संबंध में अटल जी द्वारा तय किए गए निर्णयों का अनुपालन किया।

लेखक भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री हैं
(प्रस्तुत अंश अटल बिहारी वाजपेयीः ए कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंटरियन नामक पुस्तक की प्रस्तावना से लिए गए हैं)

राफेल पर कांग्रेस गढ़ रही है झूठ का पुलिंदा

अरुण जेटली

राफेल सौदे पर बोले गए सभी झूठ उजागर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी स्पष्ट है। सरकार के खिलाफ कहा गया हर एक शब्द झूठ साबित हुआ है। सौदा के खिलाफ निहित स्वार्थों से की गई प्रत्येक टिप्पणी अब बनावटी साबित हो रही है। सत्य ने एक बार फिर अपनी प्रधानता स्थापित किया है, लेकिन इस मुद्दे पर झूठ बोलने वाले अभी भी अपनी विश्वसनीयता को दांव पर लगाकर झूठ के साथ ही खड़े हुए है और केवल उनके चहेते ही उनका साथ दे रहे हैं।

राफेल एक लड़ाकू विमान है, जिसकी खूबियां भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता में सुधार के लिए आवश्यक हैं। भारत भौगोलिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। इसे खुद को बचाने की जरूरत है। इस तरह के हथियार की जरूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जब इस तरह के रक्षा उपकरण खरीदे जाते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ कंपनियों का नुकसान होता हैं, पर इन कंपनियों में भी चतुर लोग हैं। वे समझते हैं कि भारत में "कमजोर" कौन हैं।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में राहुल गांधी का इस सौदे के विरोध में खड़ा होना उनकी हताशा को दर्शाता है। वह यूपीए सरकार थी जिसने राफेल को तकनीकी रूप से सबसे अच्छा और सस्ता विमान बताया था। एक इंटर-गवर्नमेंट समझौते में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी सरकार के साथ जो करार किया है, उसमें यूपीए सरकार द्वारा सहमत नियमों एवं शर्तों तथा मूल्यों को बेहतर ही किया गया है।

राहुल का विरोध इन तीन कारणों से स्पष्ट है:-

सबसे पहले, वह इस बात को पचा नहीं पा रहे है कि हाल के भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे साफ सरकार चलाई है। इस सरकार के कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ और बिचौलियों तथा घोटालेबाजों को देश के बाहर शरण लेनी पड़ी।

दूसरे, राहुल गांधी पर एक कलंकित विरासत का बोझ है जो बोफोर्स द्वारा दागी गई थी। वह राफेल और बोफोर्स के बीच एक 'अनैतिक समानता' लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राफेल सौदे में बिचौलिए नहीं थे, कोई रिश्वत नहीं दी गयी और जाहिर तौर पर कोई ओतावियो क्वात्रोची भी नहीं था।

तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अब यूपीए सरकार के घोटालेबाजों को भारत में प्रत्यर्पित किया जा रहा है। जाहिर है डर यह है कि कौन कितनी बात बोलेगा।

राहुल गांधी को लुटियंस दिल्ली के "कैरियर नेशनलिस्ट" का समर्थन तुरंत मिला। इन स्थायी जनहित याचिकाकर्ताओं ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं पर रुकावटों को प्राथमिकता दी है। वे भारत को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सहयोग करने को तैयार रहते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में इस एक नये रोजगार का सृजन होने लगा, जो केवल देश के खिलाफ है। इसलिए यह विघटनकारी गठबंधन काफी व्यापक है।

झूठ जो बोला गया

यूपीए द्वारा गुणवत्ता और कीमत दोनों के लिए बोफोर्स चयन किया गया था, जिसे भुला दिया गया।

इस मामले में भी पहला झूठ यह बोला गया था कि केवल एक आदमी - प्रधानमंत्री ने इस समझौते को अंजाम दिया और वायु सेना, रक्षा मंत्रालय या रक्षा अधिग्रहण परिषद के साथ इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। यह आरोप लगाया गया था कि कीमत तय करने के लिए किसी समिति का निर्माण नहीं हुआ, कोई अनुबंध वार्ता समिति नहीं बनी और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। यह हर तथ्य झूठा है। इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन कमेटी और प्राइस नेगोशिएशन कमेटी की दर्जनों बैठकें हुईं। वायु सेना के विशेषज्ञों द्वारा इन वार्ताओं में हिस्सा लिया गया और रक्षा अधिग्रहण परिषद एवं सुरक्षा पर कैबिनेट समिति दोनों की मंजूरी के बाद ही इस सौदे को किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस मामले में प्रक्रियात्मक अनुपालन की बात कही गई है और कोर्ट काफी संतुष्ट दिखाई दिया।

दूसरा बड़ा झूठ यह था कि यूपीए सरकार द्वारा 500 मिलियन यूरो की तय कीमत के खिलाफ एनडीए सरकार ने प्रति विमान 1600 मिलियन यूरो का भुगतान किया। यह इलज़ाम कोरी कल्पनाओं और एक कमजोर मूल्यांकन पर आधारित था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत किया, जिसमें यूपीए सरकार और एनडीए सरकार द्वारा तय कीमतों का एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने यूपीए के मुकाबले प्रत्येक विमान के लिए 9% और हथियारबंद विमान के लिए 20% सस्ता सौदा किया। चूंकि यूपीए ने 18 विमानों की आपूर्ति का सौदा किया था, इसलिए यह 9% और 20% का लाभ वर्तमान सौदे में और भी विस्तृत हो जाता है। न्यायालय ने कीमतों पर गौर किया और इस मामले में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की।

तीसरा बड़ा झूठ न्यायालय के निर्णय को लेकर यह फैलाया जा रहा है कि कोर्ट ने भारत सरकार को एक विशेष व्यापारिक घराने का पक्ष लेने की बात कही है। जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सरकार का ऑफसेट सप्लायर्स तय करने की प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है, इसका निर्णय पूर्ण रूप से डसॉल्ट ने किया था।

कोर्ट के फैसले के बाद इस बहस पर विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन न तो इस केस की पैरवी करने वाले और न ही हमारे राजनीतिक विरोधी इस बात को हजम कर पा रहे है।

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मांग अनुचित

राफेल सौदे का विरोध करने वाले के पास अपनी बात रखने के विभिन्न मंच थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुना।

न्यायालय बिना पक्षपात करे, स्वतंत्र और एक निष्पक्ष समीक्षा करता है और संवैधानिक तौर पर भी कोर्ट ही सर्वोच्च संस्था है। अदालत का फैसला अंतिम होता है, उसकी समीक्षा केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। एक संसदीय समिति कैसे कोर्ट के निर्णय की समीक्षा कर सकती है। क्या राजनेताओं की एक समिति कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा करने में सक्षम है? इस मामले में भी सौदे की प्रक्रिया, ऑफसेट सप्लायर्स और मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों पर क्या एक संसदीय समिति, कोर्ट ने जो कहा है, उससे अलग कोई दृष्टिकोण पेश कर सकती है? क्या राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता कर एवं दो देशों के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन कर, संसद/उसकी समिति को कीमतों की जनकारी दी जा सकती है? यह राष्ट्रीय हित के साथ गंभीर समझौता नहीं होगा? इस सौदे की कीमतें सार्वजनिक डोमेन में आ जाएगी। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने एकमात्र अवसर पर क्या किया जब उन्होंने एक रक्षा लेनदेन की जांच की?

बोफोर्स सौदे पर साल 1987-88 में बी. शंकरानंद समिति का गठन किया गया। चूंकि सांसद हमेशा अपनी पार्टी लाइन पर विभाजित होते हैं, इसलिए इस समिति ने कहा कि इस सौदे में कोई रिश्वत नहीं दी गई है तथा बिचौलियों को दिए जाने वाले पैसे को 'वाइंडिंग अप' चार्ज बताया गया। उस समय केवल विन चड्ढा को बिचौलियों के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसके बाद ओतावियो क्वात्रोची सहित अन्य लोगों की जांच में पता चला कि जबकि यह लोग किसी वाइंडिंग अप चार्ज के हकदार नहीं थे फिर भी उनकों पैसों का भुगतान किया गया। चित्रा सुब्रमणियम और एन. राम द्वारा 'द हिंदू' में प्रकाशित रिपोर्ट और उसके बाद के सभी तथ्य में पाया गया कि जेपीसी ने इस मामले में उल्लिखित प्रत्येक तथ्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है। यह केवल एक कवर अप एक्सरसाइज बन रह गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही इस मामले में भी वैधता मिली। विभिन्न अवसरों पर ऐसा पाया गया है कि अदालत ने जो कहा हो, उसके मुकाबले एक राजनीतिक निकाय कभी भी कोई अलग या बेहतर दृष्टीकोण रखने में सक्षम नहीं रही है।

मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी संसद के मौजूदा सत्र में भी राफेल पर चर्चा के बजाय गतिरोधों को ही प्राथमिकता देगी। कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निर्णायक रूप से रक्षा लेनदेन पर चर्चा में कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों को स्थापित करता है। यह कांग्रेस पार्टी की विरासत और उसके रक्षा अधिग्रहण की याद दिलाने का भी एक बड़ा अवसर होगा – वहीं हममें से कुछ लोगों के लिए बोलने का भी एक शानदार अवसर होगा।

सीएजी पर अस्पष्टता

रक्षा सौदों को ऑडिट समीक्षा के लिए सीएजी के पास भेजा जाता हैं। सीएजी की सिफारिशें संसद में जाती हैं और उसे लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास भेज दिया जाता है, जिसकी रिपोर्टें संसद के सामने रखी जाती हैं। यह तथ्य भी सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया था। राफेल की ऑडिट समीक्षा सीएजी के समक्ष लंबित है। इसके साथ ही अन्य सभी तथ्य साझा किए गए। जब इसकी रिपोर्ट तैयार होगी, तो यह पीएसी के पास जाएगी। इस तथ्यात्मक रूप से सही बयान के बावजूद, अगर कोर्ट के आदेश में अस्पष्टता सामने आई है, तो सही तरीका यह है कि कोई भी न्यायालय के समक्ष आवेदन कर, इसे सही करवा सकता है। अतीत में भी ऐसा होता रहा है, यदि किसी तथ्यपूर्ण कथन में कुछ भी सही करने की आवश्यकता है, तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय का रुख कर सकता है। यह पहले भी किया जा चुका है। अब यह बताना होगा कि सीएजी समीक्षा किस चरण में लंबित है, पर इस बात को अगर न्यायालय के विवेक पर छोड़ दें, तो ज्यादा बेहतर होगा। सीएजी समीक्षा सौदे की प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण और ऑफसेट आपूर्तिकर्ताओं पर अंतिम निष्कर्षों के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर झूठ बोलने वाले कभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। अपने झूठों प्रयासों में असफल होने के बाद अब इन लोगों ने न्यायालय के निर्णयों पर ही प्रश्नचिन्ह लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब इस निर्णय को लेकर झूठ का पुलिंदा गढ़ रही है।

मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी संसद के मौजूदा सत्र में भी राफेल पर चर्चा के बजाय गतिरोधों को ही प्राथमिकता देगी। कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निर्णायक रूप से रक्षा लेनदेन पर चर्चा में कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों को स्थापित करता है। यह कांग्रेस पार्टी की विरासत और उसके रक्षा अधिग्रहण की याद दिलाने का भी एक बड़ा अवसर होगा– वहीं हममें से कुछ लोगों के लिए बोलने का भी एक शानदार अवसर होगा। ■

(लेखक केंद्रीय वित मंत्री हैं)

राफेल मुद्दे पर जारी निरर्थक बहस

ए. सूर्यप्रकाश

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में राफेल समझौते पर विभिन्न आरोप लगाने वाली कई याचिकाओं पर अपना निर्णय दिया। इसके अंतर्गत 36 राफेल विमान एक फ्रांसीसी कंपनी से खरीदे गए थे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनता को इस मुद्दे पर वर्तमान समय में जारी शोर-शराबा समझने में आसानी होगी। कुछ क्षेत्रों में राफेल सौदे की तुलना बोफोर्स समझौते से करने के प्रयास हो रहे हैं।

फिलहाल इन दोनों समझौतों में इस तथ्य को छोड़ कर कोई समानता नहीं है कि दोनों विदेशी कंपनियों से रक्षा खरीद समझौते हैं, लेकिन यह समानता यहीं समाप्त हो जाती है। बोफोर्स के मामले में स्पष्ट आरोप थे कि स्वीडिश कंपनी ने अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी और कुछ उद्यमों को भुगतान पूरी तरह प्रमाणों के आधार पर स्थापित हो गए थे। कमीशन लेने वालों में ओट्टावियो क्वात्रोची भी शामिल था जो संप्रग अध्यक्षा सोनिया गांधी तथा उनके स्वर्गीय पति राजीव गांधी का नजदीकी दोस्त था। राफेल के मामले में रिश्वत या भ्रष्टाचार का ऐसा कोई आरोप नहीं है, हालांकि आफसेट साझीदार चयन के मामले पर सवाल उठाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं को अनेक तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया है, जिनमें से एक आरोपों की अस्पष्टता है।

दूसरी ओर, बोफोर्स के मामले में सामने आए रिश्वत के प्रमाणों पर गौर करें। इन भुगतानों के एक हिस्से को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण-आईटीएटी की दिल्ली शाखा ने दर्ज किया है। इस न्यायाधिकरण में आरपी तोलानी व आरसी शर्मा शामिल थे। न्यायाधिकरण ने एकदम सटीक तरीके से पैसे के आदान-प्रदान को दर्ज किया था तथा कई साल पहले ही अपने द्वारा निकाले नतीजे पेश किए थे। बोफोर्स मामले में भुगतान के अकाट्य प्रमाण थे और यह स्थिति वर्तमान समय में राफेल समझौते के बारे में सरकार के खिलाफ जारी शोर-शराबे व लगाए जाने वाले अस्पष्ट आरोपों से एकदम उलट है। न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया था सोनिया गांधी व राजीव गांधी का इटैलियन मित्र ओट्टावियो क्वात्रोची 4 मार्च, 1966 से 12 जून, 1968 के संक्षिप्त समय को छोड़कर 28 फरवरी, 1963 से 29 जुलाई, 1993 तक भारत में रहा था। वह पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट था तथा बहुराष्ट्रीय इटैलियन कंपनी स्नैमप्रोगेती के लिए काम करता था, लेकिन न्यायाधिकरण के अनुसार, 'स्नैमप्रोगेती या क्वात्रोची का तोपों, तोप व्यवस्थाओं या किसी प्रकार के संबंधित रक्षा उपकरणों के संबंध में कोई अनुभव नहीं था। हालांकि, राजीव गांधी सरकार ने घोषणा की थी कि सप्लायरों के एजेंट नहीं होने चाहिए, पर उसने 15 नवंबर, 1985 को ब्रिटेन की एक कंपनी एई सर्विसेज लिमिटेड से कंसल्टेंसी समझौता किया था।

यह समझौता क्वात्रोची ने कराया था। इस अनुबंध का सर्वाधिक आश्चर्यजनक आयाम यह था कि बोफोर्स ने 31 मार्च, 1986 से पहले भारत से अनुबंध होने की स्थिति में अनुबंध की कुल कीमत का तीन प्रतिशत इस कंपनी को देने का वादा किया था। यह अवधि 15 नवंबर, 1985 में समझौते पर हस्ताक्षर के 137 दिन के भीतर थी। राजीव गांधी सरकार ने बोफोर्स द्वारा निर्धारित अंतिम समय-सीमा समाप्त होने के केवल एक सप्ताह पहले 24 मार्च, 1986 को अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत सरकार ने 2 मई, 1986 को भुगतान की पहली किश्त बोफोर्स को जारी कर दी थी, जो अनुबंध का 20 प्रतिशत थी। बोफोर्स ने फौरन 3 सितंबर, 1986 को 7.343 मिलियन डालर का भुगतान ज्यूरिक के नार्डफिनेन्ज़ बैंक में एई सर्विसेज के खाता संख्या 18051-53 में कर दिया जो अग्रिम भुगतान का 3 प्रतिशत था। न्यायाधिकरण ने पता लगाया कि एई सर्विसेज को मिला पैसा 29 सितंबर,

1986 को जेनेवा के यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड में कोलबार इन्वेस्टमेंट के खाता संख्या 254.561.60डब्लू में भेजा गया। 25 जुलाई, 1988 को इस पैसे को इसी बैंक में वेटेलसेन ओवरसीज़ एसए नामक कंपनी के खाता संख्या 488.320.60 एक्स में भेजा गया। इसके बाद 21 मई, 1990 को यह पैसा चैनल आईलैंड के गुएरनसे में स्थित इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कंपनी के खाता संख्या 123984 में भेजा गया। आईटीएटी ने कहा था, 'कोलबर इन्वेस्टमेंट तथा वाटेलसन ओवरसीज़ का नियंत्रण ओट्टावियो क्वात्रोची तथा उनकी पत्नी मारिया क्वात्रोची द्वारा किया जाता था।'

लेकिन सर्वाधिक असाधारण घटनाक्रम यह था कि अप्रैल 1987 में रिश्वत स्कैंडल का खुलासा होने के बाद एई सर्विसेज़ ने एकपक्षीय रूप से घोषणा कर दी कि वह बोफोर्स से कमीशन के रूप में मिलने वाली बाकी धनराशि छोड़ देगा। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बोफोर्स द्वारा दिए संदिग्ध भुगतानों का स्पष्टीकरण देने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। अंतिम विश्लेषण में आईटीएटी ने कहा था कि क्वात्रोची व विन चड्ढा ने 243 मिलियन स्वीडिश क्रोनर प्राप्त किए थे, लेकिन रिश्वत लेने वाले क्वात्रोची तथा नेहरू-गांधी परिवार के बीच सबसे मजबूत संपर्क तब स्थापित हुआ जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश सरकार से क्वात्रोची के बैंक खाते पर लगाया प्रतिबंध हटाने को कहा जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कहने पर लगाया गया था। इससे क्वात्रोची को लूट के पैसे के साथ भागने का मौका मिल गया। भारत द्वारा सेना के लिए फील्ड तोपें खरीदने में नेहरू-गांधी परिवार के नजदीकी मित्र द्वारा रिश्वत लेने के इन अकाट्य प्रमाणों के उलट राफेल समझौते में लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल समझौते के खिलाफ पेश याचिकाओं की अनुपयुक्तता तथा प्रेस में आई खबरों पर उनकी अतिनिर्भरता के बारे में उचित टिप्पणी की है।

अदालत ने कहा है, 'हमें 36 रक्षा विमानों की खरीद के संवेदनशील मामले में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं नजर आता है। व्यक्तियों की धारणायें खासकर ऐसे मामलों में इस अदालत द्वारा जांच का आधार नहीं बन सकती हैं।' आफसेट साझीदार पसंद करने के आरोपों पर चर्चा करते हुए अदालत ने कहा है, 'केवल प्रेस साक्षात्कार या उनसे मिलने वाले संकेत इस अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं बन सकते हैं। हमें रिकार्ड पर ऐसी कोई समुचित सामग्री नहीं मिली, जिससे स्पष्ट हो कि यह मामला भारत सरकार द्वारा किसी पक्ष के प्रति वाणिज्यिक पक्षपात का है।

रिट याचिकाओं में एक महत्वपूर्ण मुद्दा विमानों की कीमत संबंधी था। वायुसेना प्रमुख ने राफेल की कीमत घोषित करने का विरोध किया था। इसके बावजूद अदालत ने उल्लेख किया कि इस हिचक के बावजूद अदालत के समक्ष ऐसी सामग्री रखी गई, जिससे वह स्वयं को संतुष्ट कर सके।' अदालत ने कहा कि उसने कीमत के विस्तृत विवरणों पर गहराई से गौर किया है और वह 'ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेगी। उसने यह भी कहा कि इस मामले की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण रूप से अदालत ने कहा कि 'बाहरी आक्रमणों का मुकाबला व उनको हतोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सैनिक शक्ति व क्षमता तथा भारत की अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करने की शक्ति निसंदेह राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा उसके लिए आवश्यक सामग्री के साथ रक्षा बलों का सशक्तीकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है।' इसलिए अदालत ने अनुभव किया कि रक्षा खरीद के ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के आयाम वही नहीं हो सकते हैं जो अन्य टेंडरों व ठेकों के मामले में होते हैं।

राफेल समझौते पर जो लोग शोर-शराबा मचा रहे हैं व निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनको अदालत के फैसले से उचित सबक सीखने चाहिए। इस लेखक ने क्वात्रोची को भुगतान किए पैसे के आदान-प्रदान पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि इस प्रकार की जांच आरोपों को उचित ठहराने के लिए आवश्यक होती है। अतः उन पार्टियों द्वारा लगाया आरोप हास्यास्पद है जो राफेल समझौते को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'बोफोर्स क्षण' होने का दावा कर रही हैं। नारेबाजी कभी प्रमाणों का स्थान नहीं ले सकती है।

राफेल समझौते पर जो लोग शोर-शराबा मचा रहे हैं व निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनको अदालत के फैसले से उचित सबक सीखने चाहिए। इस लेखक ने क्वात्रोची को भुगतान किए पैसे के आदान-प्रदान पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि इस प्रकार की जांच आरोपों को उचित ठहराने के लिए आवश्यक होती है। अतः उन पार्टियों द्वारा लगाया आरोप हास्यास्पद है जो राफेल समझौते को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'बोफोर्स क्षण' होने का दावा कर रही हैं। नारेबाजी कभी प्रमाणों का स्थान नहीं ले सकती है। ■

लेखक प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं
(वायनियर से साभार)

नेशनल हेराल्ड के नाम पर 'एक परिवार' द्वारा हेराफेरी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने 22 दिसंबर को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और नई दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी पर तीखा हमला किया।

श्री प्रसाद ने कहा कि हेराल्ड हाउस पर कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर कांग्रेस पार्टी के 'एक परिवार' द्वारा सार्वजनिक संपत्ति यानी जमीन की चोरी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अगर वहां अखबार के पब्लिकेशन के अलावा कोई और काम नहीं हो रहा, सिर्फ किराया वसूला जा रहा है तो फिर लीज जारी रखने का क्या मतलब है? कोर्ट के दो हफ्तों में हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर सरकारी जमीन पर खड़ी लगभग 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति को एक ट्रस्ट बनाकर कैसे महज 50 लाख रुपये में ट्रांसफर कर एक परिवार की संपत्ति के रूप में तब्दील किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि देश की पब्लिक प्रॉपर्टी का सोनिया जी, राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग किस तरह से दुरुपयोग करते हैं इस पर कल दिल्ली हाईकोर्ट की भी मुहर लगी है।

संपत्ति के मालिकाना हक पर कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं उस पर राहुल गांधी को जवाब देना होगा और इस पर चुप्पी से काम नहीं चलेगा।

राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि कभी दामाद श्री कुछ लाख रुपये में सैकड़ों करोड़ों के जमीन के मालिक बन जाते हैं तो कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी महज कुछ लाख रुपये में हजारों करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। ये कांग्रेस परिवार का स्कैम का नया बिजनेस मॉडल है।

श्री प्रसाद ने कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी द्वारा तथ्यों को छुपाने के लिए कई विरोधाभासी बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित इनकम टैक्स के एक मामले में गांधी परिवार एक ओर कोर्ट में बताता है कि 2008 में ही नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर जब हेराल्ड हाउस को खाली करने के निर्देश दिए जाते हैं तो गांधी परिवार कहता है कि विगत कुछ महीनों से पब्लिकेशन का काम चल रहा है। मतलब, स्पष्ट है कि गांधी परिवार किसी भी तरह से प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है, जबकि फिजिकल इंस्पेक्शन में भी पाया कि हेराल्ड हाउस में किसी भी प्रकार से अखबार के पब्लिकेशन का कोई काम नहीं हो रहा और दूसरे व्यावसायिक गतिविधियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है।

ज्ञात हो कि हेराल्ड हाउस को तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी गई थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जो जमीन एक काम के लिए एसोसियेट जर्नल्स लिमिटेड को एक तय समय के लिए लीज पर दी गई, उसे बिना संबंधित परमिशन के यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया जिसके लगभग 99% शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास हैं। इससे स्पष्ट है कि इतने प्राइम लोकेशन पर सरकारी प्रॉपर्टी को महज कुछ लाख में हड़पने की साजिश रची गई।

श्री प्रसाद ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन के पैराग्राफ 20 में कहा है कि जिस तरह से एसोसियेट जर्नल्स लिमिटेड के शेयर्स यंग इंडिया को ट्रांसफर किया गया, यह पूरी प्रक्रिया क्वेश्चनेबल है। कोर्ट ने हेराल्ड हाउस को खाली कराने के नोटिस को भी सही ठहराया है और गांधी परिवार के पिटीशन को खारिज कर दिया है।

श्री प्रसाद ने कहा कि कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हम राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं:

1. राहुल गांधी हेराल्ड हाउस को खाली करने के कोर्ट के निर्णय पर जवाब दें। चूंकि कोर्ट ने प्रॉपर्टी के गांधी परिवार और दो अन्य कांग्रेसी नेताओं के मालिकाना हक़ पर भी आपत्ति जताई है तो हम चाहेंगे कि राहुल गांधी इसका भी उत्तर दें।

2. राहुल गांधी, आप देश की जनता को यह बताइये कि आपने सरकारी जमीन पर खड़ी 5000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को किस तरह एक दिखावे के ट्रस्ट के नाम पर अपने परिवार के अंदर ट्रांसफर कर लिया?

एक ओर 'परिवार' के दामाद श्री कुछ लाख रुपये में ही सैकड़ों करोड़ों के जमीन के मालिक बन जाते हैं तो दूसरी ओर सोनिया गांधी और राहुल गांधी महज कुछ लाख रुपये में हजारों करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक़ प्राप्त कर लेते हैं। ये घपलों-घोटालों का कांग्रेस का कौन सा नया बिजनेस मॉडल है, इसे देश की जनता जानना चाहती है।

श्री प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे ट्रांजेक्शन की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के मालिकाना हक पर कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं उस पर राहुल गांधी को जवाब देना होगा और इस पर चुप्पी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि सरकारी संपत्ति की लूट किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। ■

'विपक्ष चाहे जितनी भ्रांतियां फैलाए, केंद्र में सरकार भाजपा की ही बनेगी'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 23 दिसंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में दिल्ली प्रदेश राज्य स्तरीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए दिल्ली की जनता को गुमराह करने वाली केजरीवाल सरकार पर करारा प्रहार किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, पार्टी उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के साथ-साथ प्रदेश के सभी 16 हजार बूथों से बूथ अध्यक्ष, प्रभारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि 2019 के लोक सभा चुनाव के पूर्व देश के हर प्रदेश में संभाग के हिसाब से बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होने वाले हैं और इस सम्मेलन का श्रीगणेश आज दिल्ली की सात लोक सभा सीटों के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के नायक सच्चे अर्थों में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि 2019 का लोक सभा चुनाव देश के लोकतंत्र में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति का अंत करने वाला चुनाव होगा।

सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा से कांग्रेस का चेहरा हुआ बेनकाब

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अभी एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख दंगों में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद सज्जन कुमार ने इस्तीफा दे दिया। मैं आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 1984 से लेकर आज तक सिख नरसंहार के दंगा पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सिख दंगा पीड़ितों को न्याय इसलिए नहीं मिला, क्योंकि दंगे कराने वाले ही दोषियों के संरक्षक बने हुए थे। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी गठित कर जांच शुरू की गई, जिसके बाद आज एक के बाद एक केस में दंगा पीड़ितों को न्याय मिल रहा है और दोषी कांग्रेसियों को सजा हो रही है। उन्होंने कहा कि दंगे के खिलाफ भाषण देने का दिखावा करने वाले कांग्रेसियों का दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र अदालत के सामने बेनकाब हो गया है और यह सिद्ध हो गया है कि सिख दंगे तत्कालीन

सत्ताधीशों की निगरानी में ही थे, सिखों पर अत्याचार कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया था।

मोदी सरकार ने उठाये सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कई कदम

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कई कदम उठाये। पांच लाख रुपये का मुआवजा देना, एसआईटी का गठन करना और अदालतों में इस प्रकार के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रखना, जो न्याय के पक्ष में दलीलें दे और सजा दिलाकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में मददगार हो - कुछ ऐसे ही कदम हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 1984 के सिख नरसंहार में मारे गए 3300 लोगों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। दिल्ली विधान सभा में एक दिन पहले ही पारित हुए प्रस्ताव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा की

घटना आम आदमी पार्टी द्वारा सिख दंगा पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को!

अरविन्द केजरीवाल के झूठे वादे बने केजरीवाल सरकार की विफलताओं की सूची

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में मुख्यतः तीन पार्टियों के बीच में लड़ाई है - भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल और राहुल गांधी ने झूठ की राजनीति की पराकाष्ठा को पार कर लिया है। इसके बावजूद आज भी सच छुपाने के लिए दोनों झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से कई वादे कर सत्ता में आई थी, लेकिन आज उनके वादे उनकी विफलता की सूची बन कर रह गए हैं। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है लेकिन केजरीवाल इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले आम आदमी बनकर घूमने वाले आज जेड प्लस सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 500 नए विद्यालयों को खोलने की बात की थी, लेकिन देश की जनता आज यह जानना चाहती है कि ये 500 विद्यालय कहां हैं? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हर लोक सभा क्षेत्र में अस्पताल खोलने का वादा किया था लेकिन अस्पताल नजर नहीं आ रहे। अस्पताल की जगह जो मोहल्ला क्लीनिक बनाये गए हैं वहां न तो डॉक्टर है और न दवाई, कभी-कभी तो मोहल्ला क्लीनिक में जानवर भी बैठे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली का युवा हाथों में मोबाइल लिए फ्री वाई-फाई ढूंढ रहा है लेकिन केजरीवाल की वाई-फाई और उसकी कनेक्टिविटी ढूंढें से भी दिल्ली में नहीं मिलती। अरविन्द केजरीवाल ने डीटीसी बसों में महिला मार्शल की व्यवस्था की बात की थी, लेकिन आज तक इसकी तैनाती नहीं हुई। केजरीवाल कम-से-कम मार्शल का ड्रेस कोड ही बता दें ताकि दिल्ली की आम जनता बसों में सुरक्षित महसूस कर सकें। आम आदमी पार्टी द्वारा सीसीटीवी लगाने का भी एलान किया गया था, लेकिन इसका कोई अता-पता नहीं है। पेयजल की व्यवस्था सुधारने की भी बात की गई थी लेकिन दिल्ली की लगभग आधी आबादी दुर्गंध वाला पानी पीने को मजबूर है। अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ऐसी न जाने कितनी योजनायें हैं जो आज तक पूरी ही नहीं हुई।

दिल्ली के विकास के लिए भाजपा सदैव तत्पर

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली की 16 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को मंजूरी देने का काम किया है। दिल्ली-मेरठ हाइवे का निर्माण किया गया। ईस्टर्न कॉरिडोर में अलग-अलग सड़क योजनाओं के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये दिए गए। आईपी विश्वविद्यालय को भी स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त अमृत प्रकल्प के तहत दिल्ली की चार स्थानीय निकायों को लगभग 802 करोड़ रुपये दिए गए, स्मार्ट सिटी योजना के तहत 71 प्रोजेक्ट्स के लिए 1331 करोड़ रुपये दिए गए और पूरे दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो का जाल बिछाने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी है जो वादों को पूरा कर जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जो वादे तो कभी पूरे करते नहीं और उस पर नए-नए झूठे वादे करते जाते हैं।

राहुल गांधी की झूठ की राजनीति को बेनकाब करें पार्टी कार्यकर्ता

हेराल्ड हाउस को खाली कराने संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कल ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली की नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग को 15 दिनों में खाली करने का निर्देश दिया है। जनता की संपत्ति को पिछले रास्ते से कांग्रेसी नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत कंपनी में तब्दील कर करोड़ों-अरबों रुपये की संपत्ति को हड़पने की साजिश रची थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निर्णय से विफल कर दिया है। उन्होंने कहा

कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगभग 600 करोड़ रुपये की आय को छुपाने के लिए भी इनकम टैक्स ने नोटिस दिया हुआ है, इसे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरह से सर्टिफाई करने का काम किया है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व खुद तो 5000 करोड़ रुपये के फ्रॉड में जमानत पर है, लेकिन इसके बावजूद झूठे आरोप लगाने से ये बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि राफेल डील पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जब पूरे देश में हो-हल्ला कर रही थी, तब भी हमने उनसे कहा था कि आपके पास जो भी तथ्य हो, साक्ष्य हों, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाइए जहां आपकी ही 'बी' टीम राफेल पर सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना उचित नहीं समझा क्योंकि उन्हें पहले से ही मालूम था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि किसी भी आरोपों में कोई दम नहीं है और इसकी जांच करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद निर्लज्जता से कांग्रेस पार्टी उसी झूठ को दोहराने में लगी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि अरबों-खरबों का घपला-घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार पर झूठे और अनर्गल आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता दिल्ली के घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करे और कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करे।

देश में फिर से श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह है। हर जगह 'मोदी-मोदी' के नारे गूंज रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि विपक्ष चाहे जितनी भ्रांतियां फैलाए, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश बना सुरक्षित, समृद्ध और मजबूत

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। उरी हमले में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों की कायराना हरकत का जवाब हमने 'सर्जिकल स्ट्राइक' के जरिये दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी देश की सुरक्षा के सवाल पर देश को असुरक्षित करने वाले तत्वों के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में असम में एनआरसी बनाने की शुरुआत की, ताकि अवैध घुसपैठियों को चिह्नित किया जा सके लेकिन कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी को देश के नागरिकों के बजाय अवैध घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता सताने लगी। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको बम धमाकों में मारे जाने वाले लोगों के परिवार के मानवाधिकार की चिंता नहीं है? गरीब देशवासियों के मानवाधिकार की चिंता नहीं है? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करके पुनः लोकप्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन करें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर कच्छ तक अवैध घुसपैठियों को चुन-चुन कर देश से बाहर निकालने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठिये देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है और हम ऐसे गंभीर विषयों पर समझौता नहीं कर सकते।

गरीबों के कल्याण के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक लगभग 55 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात तो करती है, लेकिन आज तक उसने गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने देश के गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का ख़याल रखते हुए लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू किया है, जिसके तहत हर गरीब को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त दिया जाएगा लेकिन केजरीवाल सरकार इस योजना को दिल्ली में लागू ही नहीं कर रही क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में 6 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया है, 8 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया है, लगभग 19 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई है और अगले 26 जनवरी तक देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प लेकर भाजपा सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश से नक्सलवाद और माओवाद को भी ख़त्म करने के प्रयास किये गए हैं। लगभग 32 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले गए हैं, स्मार्ट सिटी योजना को लागू किया गया है और किसानों को उनकी फसल पर लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया गया है।

श्री शाह ने कहा कि देश में फिर से श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह है। हर जगह 'मोदी-मोदी' के नारे गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि विपक्ष चाहे जितनी भ्रांतियां फैलाएं, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली की सातों सीटों पर भाजपा को विजयश्री सुनिश्चित करने हेतु एकजुट हो जाने की अपील की। ■

2014 के बाद से पूर्वोत्तर में विद्रोह की घटनाओं में 63 प्रतिशत की गिरावट

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018 में आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य बेहद शांतिपूर्ण रहा। बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के साथ सीमाओं पर स्थिति में काफी सुधार हुआ। पश्चिमी सीमाओं पर हमारे सुरक्षा बलों ने युद्धविराम उल्लंघनों का उतने ही कड़े तौर पर जवाब दिया और घुसपैठ के प्रयासों को विफल किया। जम्मू एवं कश्मीर में ठोस आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया हुआ और स्थानीय निकाय चुनावों का निर्विघ्न संचालन हुआ।

पूर्वोत्तर में पिछले चार वर्षों के दौरान सुरक्षा परिदृश्य में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है, जिसके नतीजतन इस साल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को हटा दिया गया। असम में बिना किसी हिंसा के ड्राफ्ट राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जारी कर दिया गया और अंतिम एनआरसी आने वाला है। देश के आंतरिक इलाकों में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिले 2013 में जहां 76 थे वो अब सिकुड़कर 58 रह गए हैं।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट बाड़ की दो पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की गई। आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) के अंतर्गत एक एकल अंक वाले अखिल भारतीय आपातकालीन फोन नंबर '112' को लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में की गई है। गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मसलों को संबोधित करने के लिए एक नया विभाग बनाया है, वहीं दो पोर्टलों 'महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध निवारण' (सीसीपीडब्ल्यूसी) और 'यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस' (एनडीएसओ) ने भी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विषयों को और आगे बढ़ाने का काम किया है।

इसके अलावा गुजरे साल में गृह मंत्रालय ने जो अन्य काम किए हैं उनमें - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में केंद्र के हिस्से को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना, ई-वीज़ा की जबरदस्त सफलता, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर भारत-चीन के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन, क्षेत्रीय परिषदों की नियमित बैठकों का संचालन, प्रधानमंत्री के हाथों राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाना और नए स्थापित किए गए पुलिस मैडल जैसी सुर्खियां भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां निम्न हैं:

जम्मू एवं कश्मीर

कश्मीर घाटी में पत्थरबाज़ी की बार-बार होने वाली घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने मई 2018 में रमजान के पावन महीने के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में सभी ऑपरेशनों को रोकने की घोषणा करते हुए एक प्रमुख समाधानकारक पहल की। हालांकि एक समीक्षा के बाद इसे रमजान की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ठोस आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों को शुरू किया जिसके महत्वपूर्ण नतीजे मिले। इस साल 2 दिसंबर 2018 तक 587 घटनाओं में 238 आतंकवादी मारे गए और सुरक्षा बलों के 86 व्यक्ति शहीद हुए व 37 नागरिकों की जान गई। जून में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के लिए दो महिला बटालियन खड़ी करने को अपनी स्वीकृति दी।

शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर में सुरक्षा परिदृश्य लगातार सुधर रहा है। वर्ष 1997 के बाद से पिछले दो दशकों में पहली बार पिछले साल विद्रोह की घटनाएं और सुरक्षा बलों व नागरिकों के बीच हताहतों की संख्या सबसे कम दर्ज की गईं। जहां त्रिपुरा और मिजोरम में अब करीब करीब कोई विद्रोह नहीं बचा है, वहीं अन्य राज्यों और इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार देखा गया है।

2014 के बाद से चार वर्षों में इस क्षेत्र में विद्रोह की घटनाओं में 63 प्रतिशत की गिरावट आई है। ठीक इसी तरह 2014 की तुलना में 2017 में यहां नागरिकों की मौतों में 83 प्रतिशत और सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या में 40 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई है।

इसके अलावा 31 मार्च को मेघालय के सभी इलाकों से सशस्त्र

बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को हटाया जाना पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य में विस्तृत सुधार का सजीव उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश में भी आफस्पा के दायरे में आने वाले इलाकों को, असम सीमा से लगे 16पीएस/चौकी क्षेत्रों से घटाकर तिरप, चैंगलांग और लॉन्गडिंग जिलों के साथ 8 पुलिस स्टेशनों तक कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 28 अप्रैल के प्रभाव से एनएससीएन/एनके और एनएससीएन/आर के साथ युद्धविराम एक साल के लिए और बढ़ा दिया है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का ड्राफ्ट जारी

बिना किसी घटना के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी-ड्राफ्ट) को जारी किया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 25 जुलाई को गृह मंत्रालय ने असम राज्य सरकार और पड़ोसी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए कि वे 30 जुलाई 2018 को जारी होने जा रहे ड्राफ्ट एनआरसी से पहले और प्रकाशन के बाद में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सुनिश्चित करें। असम में ड्राफ्ट एनआरसी के प्रकाशन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 और 30 जुलाई को दो अलग-अलग बयान जारी किए और आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और सभी के साथ मानवीय तौर पर व्यवहार किया जाएगा।

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र सिकुड़े

पिछले चार वर्षों में वामपंथी अतिवाद के परिदृश्य में ठोस सुधार आया है। हिंसा की घटनाओं में तीखी गिरावट हुई है और वामपंथी अतिवाद से होने वाली हिंसा का भौगोलिक फैलाव भी जहां 2013 में 76 जिलों में था, वह अब सिर्फ 58 जिलों तक सीमित रह गया है। इसके अलावा इनमें से सिर्फ 30 जिले ऐसे हैं जो पूरे देश में 90 फीसदी वामपंथी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं।

सीमा प्रबंधन : स्मार्ट सीमा बाड़ की शुरुआत

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 सितंबर को जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग की दो पायलट परियोजनाओं का उद्घाटन किया। व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के अंतर्गत बनने वाली ये स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग परियोजनाएं देश में अपनी तरह की पहली हैं। इन दोनों परियोजनाओं में प्रत्येक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5.5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र पर लगी हैं। इन पर हाइ-टेक निगरानी प्रणाली लगी है जो जमीन, जल, हवा और जमीन के नीचे बिजली का एक अदृश्य अवरोध पैदा करती है और सबसे कठिन इलाकों में घुसपैठ की कोशिशों को खोज निकालने व उन्हें असफल करने में बीएसएफ को मदद मिलती है। सीआईबीएमएस को ऐसे जमीनी हिस्सों पर चौकसी करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां दुर्गम भूभाग या नदी तटीय सीमाओं की वजह से भौतिक निगरानी रखना संभव नहीं है।

पिछले चार वर्षों में वामपंथी अतिवाद के परिदृश्य में ठोस सुधार आया है। हिंसा की घटनाओं में तीखी गिरावट हुई है और वामपंथी अतिवाद से होने वाली हिंसा का भौगोलिक फैलाव भी जहां 2013 में 76 जिलों में था, वह अब सिर्फ 58 जिलों तक सीमित रह गया है। इसके अलावा इनमें से सिर्फ 30 जिले ऐसे हैं जो पूरे देश में 90 फीसदी वामपंथी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं।

महिला सुरक्षा

महिलाओं की सुरक्षा सभी के लिए चिंता का विषय है और सरकार के प्रयासों को सही दिशा में लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने मई में एक नया विभाग बनाया, जो विस्तृत तौर पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मसलों को संबोधित करेगा। ये विभाग सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय रखते हुए महिला सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का सामना करता है। ऐसा माना गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए, जिसमें भागीदार मंत्रालयों/विभागों की हिस्सेदारी हो जो एक तय समय सीमा में विशेषीकृत कदम उठाएं। इसमें विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें (एफटीसी) स्थापित करना, फोरेंसिक ढांचे को मजबूत करना, यौन अपराधियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री निर्मित करना, अतिरिक्त सरकारी अभियोजन पक्ष नियुक्त करना और पीड़ितों को उचित चिकित्सकीय व पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। ■

गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां

- असम में एनआरसी शांतिपूर्ण तरीके से जारी
- वामपंथी अतिवाद के परिदृश्य में सुधार
- पश्चिमी सीमा पर स्मार्ट बाड़
- पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों से आफस्पा हटाया गया
- एकल अंक वाले अखिल भारतीय आपातकालीन फोन नंबर '112' की शुरुआत
- द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर पहला भारत-चीन समझौता
- राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का अनावरण

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड में संशोधन हुआ

मुख्य बातें

- दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिसूचित
- कंपनियों की वित्तीय जानकारी देने की प्रक्रिया में निवेशकों और जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) गठित
- कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 लागू; कुल 93 धाराओं में से 92 धाराओं को प्रासंगिक नियमों के साथ लागू किया गया
- विभिन्न प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने के लिए ई-शासन पहलों की शुरुआत

सभी हितधारकों को अधिक व्यापार सुगमता प्रदान करने, कार्पोरेट ढांचे में अधिक पारदर्शिता लाने और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कुशलता बढ़ाने के संबंध में बेहतर कॉर्पोरेट अनुपालन के उद्देश्य से कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने पिछले एक साल (जनवरी-नवम्बर, 2018) के दौरान कई बड़ी पहलें/ फैसले किए।

इनमें कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन, दिवाला और शोधन अक्षमता कोड में संशोधन, सभी कंपनियों के निदेशकों के लिए ई-केवाईसी अभियान, निगमीकरण संबंधी आवेदनों के लिए प्रक्रियाओं को तेज बनाना, नियमों के अनुपालन में समानता और विवेकाधिकार को समाप्त करना शामिल है।

31 अक्टूबर, 2018 को जारी होने वाली विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस' 2019 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 23 पायदान चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2017 में वह 100वें स्थान पर था। इस तरह भारत ने व्यापार शुरू करने और व्यापार करने के संबंध में 10 मानदंडों में से 6 मानदंडों में अपनी स्थिति में सुधार किया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने व्यापार शुरू करने, दिवाला समस्या का हल करने और अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा करने में बहुत योगदान दिया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष भर की मुख्य उपलब्धियां निम्न हैं:

दिवाला और शोधन अक्षमता

वर्ष 2018 में राष्ट्रपति ने दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जारी किया। 2017 से दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रभावी होने की शुरुआत हुई है और यह कानून बेहतर हो रहा है। नए कोड के प्रभावी होने का प्रमुख कारण न्यायपालिका द्वारा विवादों का फैसला करना है। कोड में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस कोड से ऐसी प्रक्रियाएं विकसित हुई है जिससे कानूनी अनिश्चितता में कमी आई है।

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की अधिसूचना 19 जनवरी, 2018 को जारी की गई। इसने आईबीसी (संशोधन) अधिनियम का स्थान लिया। कोड में व्यक्तियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में समाधान योजना प्रस्तुत करने का निषेध किया गया है। दिवाला विधि समिति की अनुशंसाओं के तहत अगस्त, 2018 में अध्यादेश में दूसरा संशोधन किया गया। 6 जून, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से कोड में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया। कोड में संशोधन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों विशेषकर घर खरीदने वालों, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों आदि

के हितों को संतुलित करना था। कॉर्पोरेट कर्जदारों को दिवालियापन घोषित के स्थान पर समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए ऋणदाताओं के मताधिकार के मूल्य को कम किया गया। समाधान प्रस्तुत करने वालों की योग्यता से जुड़े प्रावधानों में एकरूपता लाई गई।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

कॉर्पोरेट क्षेत्र में लेखा घोटालों और धोखाधड़ियों को देखते हुए लेखा परीक्षण के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) को एक स्वतंत्र नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया। यह कम्पनी अधिनियम 2013 में किया गया एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्राधिकरण कम्पनियों के वित्तीय सूचना की गुणवत्ता की समीक्षा करेगा और उन लेखा परीक्षकों/लेखा कम्पनियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिन्होंने अपने वैधानिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया है।

आशा है कि इस निर्णय से विदेशी/घरेलू निवेश बढ़ेगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन से लेखा परीक्षण क्षेत्र का विकास होगा तथा लेखा क्षेत्र के वैश्वीकरण को समर्थन मिलेगा। अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत प्राधिकरण को लेखा परीक्षकों (सीए) और उनकी कम्पनियों, सूचीबद्ध कम्पनियों तथा गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनियों की जांच करने का अधिकार दिया गया है।

31 अक्टूबर, 2018 को जारी होने वाली विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस' 2019 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 23 पायदान चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2017 में वह 100वें स्थान पर था। इस तरह भारत ने व्यापार शुरू करने और व्यापार करने के संबंध में 10 मानदंडों में से 6 मानदंडों में अपनी स्थिति में सुधार किया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने व्यापार शुरू करने, दिवाला समस्या का हल करने और अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा करने में बहुत योगदान दिया है।

ई-प्रशासन

त्वरित और पारदर्शी प्रक्रियाओं के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय ने व्यापार में आसानी तथा मानकीकरण के लिए कई निर्णय लिए हैं। 'रन की शुरुआत- अनूठा नाम आरक्षित करे'- नाम के लिए वेब सेवाः वेब आधारित एक सेवा की शुरुआत की गई। इसका नाम रन (आरयूएन) है- अनूठा नाम आरक्षित करे। नाम आरक्षण की प्रक्रिया को तेज, आसान और त्वरित बनाने के लिए 26 जनवरी, 2018 को इस सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा के द्वारा प्रक्रियाओं की संख्या में कमी लाई गई है। यह सेवा कम्पनियों के लिए हैं। 2 अक्टूबर, 2018 से यह सेवा एलएलपी (सीमित देयता साझेदारी) के लिए भी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

दिवाला एवं शोधन अक्षमता के समाधान से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए एमसीए ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अंतर्गत 8 विशेष अदालतें गठित करने का प्रस्ताव रखा ताकि दिवालियापन से जुड़े मामलों से निपटा जा सके। इन अदालतों को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरण पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है बावजूद इसके कि उसकी देश भर में 11 शाखाएं हैं। आईबीसी मामलों का समय पर समाधान करने के लिए दिल्ली, मुंबई की एनसीएलटी शाखाओं के अंतर्गत शुरुआत के लिए विशेष आईबीसी अदालतें स्थापित करने की परिकल्पना की गई। इसका मकसद एनपीए के तेजी से समाधान के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।

भारतीय लेखाविधि मानक

लेखाविधि में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, एमसीए ने भारतीय लेखाविधि मानक (आईएनडी एएस) 115 अधिसूचित किया जो 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया। आईएनडी एएस 115 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की तर्ज पर ग्राहकों से संपर्क बनाने के लिए एक नया राजस्व स्वीकृति मानक है, जो राजस्वों की अधिक पारदर्शी लेखाविधि में मदद करेगा और इसका प्रौद्योगिकी, रियल एस्टेट और दूरसंचार सहित विविध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों पर असर पड़ेगा।

आईएनडी एएस 115 का उद्देश्य ऐसे सिद्धांत स्थापित करना है, जिन्हें वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता उपयोगी जानकारी देते समय प्रयोग में ला सकें। इसमें किसी कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्व को स्वीकृति प्रदान करे, ताकि ग्राहकों को वस्तुओं अथवा सेवाओं का हस्तांतरण उतनी राशि में दिखाया जा सके जिसका वादा किया गया है। यह उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसकी वस्तुओं अथवा सेवाओं के आदान-प्रदान में कंपनी अपेक्षा करती है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण ने 2018 में अपने नये प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, ताकि मजबूत उपस्थिति और पहचान प्रदान की जा सके। आईईपीएफ प्राधिकार ने सीएससी ई-शासन सेवाएं भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जहां सीएससी अन्य कार्यों के अलावा निवेश जागरूकता परियोजना के लिए ग्राम स्तर के उद्यमों की पहचान करेगा। आईपीएफ में और सुधारों पर सक्रियता से एमसीए नजर रखे हुए हैं। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में स्मारक सिक्के जारी करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, साथ में– भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली और डॉ. महेश शर्मा

नई दिल्ली स्थित संसद भवन में 2001 में संसद पर हुए आंतकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पूणे (महाराष्ट्र) में मेट्रो फेज 3 की आधारशिला रखने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फणनवीस व अन्य

मुंबई (महाराष्ट्र) में 'टाइमलेस लक्ष्मण' पुस्तक का विमोचन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फणनवीस व अन्य

नई दिल्ली में जम्मू–कश्मीर के नवनिर्वाचित पंचायत सरपंचों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रयागराज स्थित बमरौली हवाई अड्डे के नए एअरपोर्ट काम्प्लेक्स का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20